



दक्षिण भारत राष्ट्रमत

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರಮತ | ಹಿಂದಿ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ | बंगलूर और चेन्नई से एक साथ प्रकाशित



5 हताशा में कांग्रेस जनगणना 2027 के बारे में 'झूठा' प्रचार कर रही : माजपा

6 अतीत में मिले नाजी दंश को कमी नहीं भूलते यहूदी

7 आजकल की कॉमेडी फिल्मों में बार-बार दोहराई जा रहे जोस और पंचलाइन : काजोल

फ़र्स्ट टेक

'आधार' अद्यतन करने की मुपत ऑनलाइन सुविधा एक साल बड़ी हुई दिल्ली/भाषा। नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या 'आधार' जारी करने वाले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने दस्तावेजों को मुपत में ऑनलाइन अद्यतन करने की सुविधा 14 जून, 2026 तक बढ़ाने की घोषणा की है। यूआईडीएआई ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह मुपत सेवा 'माईआधार' पोर्टल पर उपलब्ध है। उसने आधार धारकों से उनकी जनसांख्यिकीय जानकारी की सटीकता बनाए रखने के लिए विवरण को अद्यतन करने का आग्रह किया। प्राधिकरण ने कहा, यूआईडीएआई ने लाखों आधार संख्या धारकों को लाभ पहुंचाने के लिए मुपत ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड सुविधा 14 जून 2026 तक बढ़ा दी है। यह मुपत सेवा केवल माईआधार पोर्टल पर उपलब्ध है। यूआईडीएआई लोगों को अपने आधार में अद्यतन दस्तावेज रखने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है।

141 साल पुराने विस्फोटक अधिनियम को निरस्त कर सरकार लागू नया कानून नई दिल्ली/भाषा। सरकार 141 साल पुराने विस्फोटक अधिनियम 1884 को निरस्त कर एक नया कानून लागू करेगी। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून पुराने ब्रिटिश पैटर्न पर आधारित है और यह देश की बढ़ती आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा नहीं कर रहा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने इस वर्ष 17 जुलाई से पहले प्रस्ताव पर आम जनता, उद्योग संघों और अन्य संबंधित संस्थाओं से टिप्पणियां और सुझाव मांगे हैं। डीपीआईआईटी ने कहा है कि विस्फोटक अधिनियम, 1884 संविधान से पहले का अधिनियम है और इसे 1978 में व्यापक रूप से संशोधित किया गया था।

टिकटों के बेचने की समयसीमा बढ़ाएंगे ट्रंप वॉशिंगटन/एपी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि वह टिकटों के चीनी मालिकों के लिए लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग ऐप बेचने की समयसीमा बढ़ा सकते हैं। अमेरिकी मालिकों को ऐप बेचने के संभावित सौदे के ठंडे बरतने में जाने के बाद ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में टिकटों को 75 दिनों के लिए चालू रखने के आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। एक बार फिर समयसीमा बढ़ाने के बारे में संवाददाताओं के सवाल पर उन्होंने कहा, "शायद हां।" उन्होंने कहा, "शायद चीन की मंजूरी लेनी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि हम इसे पूरा कर लेंगे। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शी आंखिकार इसकी मंजूरी देना।"

भाषाओं के आधार पर विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकता भारत : उपराष्ट्रपति

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

पुडुचेरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को कहा कि भारत दुनिया का एक महत्वाकांक्षी राष्ट्र है और वह भाषा के मुद्दे पर विभाजन बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने लोगों से देश के भविष्य की भलाई पर विचार करने और इस 'तूफान से उबारने' की अपील की। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को अक्षरशः लागू करने की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि यह शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगी, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी। धनखड़ पिछलेरी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति भी हैं। उन्होंने किसी का नाम लिए बिना इस बात पर अफसोस जताया कि भाषाओं को लेकर विरोध हो रहा है। विश्वविद्यालय में धनखड़ ने कहा, "पिछले दशक में अभूतपूर्व विकास के परिणामस्वरूप भारत



- दुनिया में कोई भी देश भाषाओं के मामले में भारत जितना समृद्ध नहीं है।
- संस्कृत का वैश्विक महत्व है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया के साथ 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं।

दुनिया का सबसे महत्वाकांक्षी राष्ट्र है। हम भाषाओं को लेकर कैसे विभाजित हो सकते हैं?" उन्होंने कहा कि दुनिया में कोई भी देश भाषाओं के मामले में भारत जितना समृद्ध नहीं है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संस्कृत का वैश्विक महत्व है और तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया, मराठी, पाली, प्राकृत, बंगाली और असमिया के साथ 11 शास्त्रीय भाषाएं हैं। धनखड़ ने कहा,

"संसद में सदस्यों को 22 भाषाओं में बोलने की अनुमति है। हमारी भाषाएं समावेशिता का संकेत देती हैं। सनातन एक ही महान उद्देश्य के लिए एकजुट होना सिखाता है।" उन्होंने कहा, "हमारे गंतव्य को देखें, भविष्य को ध्यान में रखें और हमें तूफान से उबरना चाहिए।" एनईपी पर, उपराष्ट्रपति ने इसे नहीं लागू करने वाले राज्यों से कहा कि वे नीति को लागू करें क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति "महत्वपूर्ण बदलाव" लाएगी। उन्होंने कहा, "मैं उन राज्यों से अपील करता हूँ जिन्होंने इसे नहीं अपनाया है और जो इसे लागू कर रहे हैं, वे नीति में दी गई बातों को समझें। कार्यशालाओं के माध्यम से छात्रों को नीति के लाभ के बारे में पूरी तरह से अवगत कराए।" धनखड़ ने कहा कि एनईपी दुनिया की सबसे अच्छी नीति है क्योंकि यह छात्रों को अपनी प्रतिभा और क्षमता का पूरा दोहन करने के अलावा कई पाठ्यक्रमों को आगे बढ़ाने और समय का अधिकतम उपयोग करने का अवसर देती है।

अमेरिका जानता है कि ईरान के शीर्ष नेता खामेनेई कहां छिपे हैं : ट्रंप ट्रंप ने ईरान को बिना शर्त आत्मसमर्पण करने को कहा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com



वॉशिंगटन/एपी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका जानता है कि ईरान के शीर्ष (धार्मिक) नेता अयातुल्ला अली खामेनेई कहां छिपे हैं, लेकिन वह फिलहाल उन्हें मारना नहीं चाहता। ट्रंप ने मंगलवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ईरान से बिना शर्त आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया, क्योंकि पांच दिन से जारी संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। ट्रंप ने कहा, हमें अच्छी तरह पता है कि तथ्यांकित सर्वोच्च नेता कहां छिपे हैं।

तेहरान के प्रति ट्रंप की भाषा पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गई है। ट्रंप की ये कठोर टिप्पणियां उस समय आईं हैं जब ट्रंप ने तेहरान के 95 लाख निवासियों से अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़ने की अपील की है और एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की अपनी यात्रा बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन लौट आए ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ आपात बैठक कर सकें। ट्रंप ने कहा, वह एक आसान निशाना हैं, लेकिन वहां सुरक्षित हैं, हम उन्हें अभी मारने नहीं जा रहे हैं, कम से कम फिलहाल तो नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी जाएं। हमारा संयम अब ज्यादा दे रहा है।

का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह हो जाना चाहिए। ट्रंप ने कहा, उन्हें समझौता करना चाहिए था। मैंने कहा था, 'समझौता करो।' तो मैं अब ज्यादा बातचीत के मूड में नहीं हूँ। ईरान ने कई बार कहा है कि उनका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ शांतिपूर्ण है और अमेरिकी खुफिया एजेंसियां भी मानती हैं कि वे सक्रिय रूप से परमाणु बम नहीं बना रहे। ट्रंप ने कनाडा में जारी जी-7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर वॉशिंगटन रवाना होने से पहले सोमवार रात को एक संदेश में लिखा, "ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता।" उन्होंने अपने संदेश में कहा, "सभी को तेहरान तत्काल खाली कर देना चाहिए।" बाद में ट्रंप ने इस बात से इन्कार किया कि वह संघर्ष विराम पर काम करने के लिए जल्दबाजी में लौटे हैं। वॉशिंगटन लौटते समय एयर फोर्स वन में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा, मैं संघर्ष विराम की तरफ नहीं देख रहा हूँ।

प्रधानमंत्री मोदी जी-7 शिखर सम्मेलन के लिए कनाडा पहुंचे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

कैलगरी (कनाडा)/भाषा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि वह कनाडा के कर्नेलिनसिस में जी-7 शिखर सम्मेलन में वैश्विक नेताओं से मुलाकात के दौरान महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे तथा 'ग्लोबल साउथ' की प्राथमिकताओं पर जोर देंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सोमवार शाम को यहां पहुंचे और यह एक दशक में मोदी की कनाडा की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री इस दौरान विश्व के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे और ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी तथा नवाचार सहित महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। मोदी ने सोमवार शाम को एक पोस्ट में कहा, "जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कनाडा के कैलगरी पहुंच गया हूँ। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक



मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा।" 'ग्लोबल साउथ' शब्द का इस्तेमाल आम तौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के निमंत्रण पर साइप्रस से सोमवार शाम (स्थानीय समयानुसार) कनाडा पहुंचे। कर्नेलिनसिस में यह सम्मेलन 16 जून से 17

पश्चिम बंगाल सरकार की ओबीसी आरक्षण अधिसूचना पर अंतरिम रोक

कोलकाता/भाषा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा ओबीसी-ए और ओबीसी-बी श्रेणियों के तहत 140 उपवर्गों को आरक्षण के संबंध में जारी अधिसूचनाओं पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति तपन चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ ने 31 जुलाई तक अंतरिम रोक लगाते हुए निर्देश दिया कि राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणियों के संबंध में आठ मई से 13 जून के बीच जारी की गई कार्यकारी अधिसूचनाएं उस तिथि तक प्रभावी नहीं होंगी। अदालत ने निर्देश दिया कि इसके परिणामस्वरूप होने वाले सभी कार्य भी 31 जुलाई तक स्थगित रहेंगे। अदालत ने मामले से जुड़े सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे इस बीच जन्हित याचिका में ओबीसी श्रेणियों के तहत शामिल करने के उद्देश्य से नए मानक सर्वेक्षणों और अधिसूचनाओं को चुनौती देने के संबंध में अपनी दलीलों पर हलफनामा दाखिल करें।

एअर इंडिया में दिक्कतें: सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com



मुंबई/कोलकाता/भाषा। टाटा समूह के स्वामित्व में साढ़े तीन साल पहले आई एअर इंडिया संभवतः अपने सबसे बड़े संकट का सामना कर रही है और एयरलाइन की उड़ानें मुश्किलों से गुजर रही हैं। मंगलवार को विभिन्न कारणों से जहां उसकी सात अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं, वहीं सैन फ्रांसिस्को-मुंबई उड़ान में तकनीकी गड़बड़ी के कारण यात्रियों को बीच में ही विमान से उतरना पड़ा। विमानन कंपनी ने कहा कि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा झीमलाइनर बेड़े की कड़ी जांच किए जाने के कारण एअर इंडिया ने छह अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दीं, जबकि अहमदाबाद-लंदन गैटविक उड़ान को विमान की अनुपलब्धता के कारण रद्द कर दिया गया। दिल्ली-पेरिस उड़ान को उड़ान-पूर्व जांच के दौरान कुछ

समस्याओं का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया। रद्द की गई अन्य उड़ानों में बंगलुरु-लंदन, लंदन-अमृतसर, दिल्ली-वियना, दिल्ली-दुबई और मुंबई-सैन फ्रांसिस्को शामिल हैं। इसके अलावा, एअर इंडिया ने अपनी सैन फ्रांसिस्को-मुंबई उड़ान के एक इंजन में तकनीकी खराबी आने के कारण मंगलवार सुबह इसे कोलकाता में निधार्ित उहराव पर ही समाप्त कर दिया। सेवा में यह व्यवधान ऐसे समय में हुआ है जब अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि 12 जून को लंदन जा रही एअर इंडिया की उड़ान अहमदाबाद से रवाना होने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त क्यों हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार और जमीन पर मौजूद 270 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना से एयरलाइन और उसके मालिक टाटा समूह को गहरा झटका लगा है, जो लक्जरी कारों से लेकर मक और सांफटेजवर के साथ-साथ आईफोन तैयार करने पर गहरा करता है।

अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने कहा इजराइली हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु स्थल को नुकसान पहुंचा

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

दुबई/एपी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने मंगलवार को कहा कि उसका मानना है कि ईरान के नतांज संवर्धन स्थल पर इजराइल के हवाई हमलों का यहां के भूमिगत सेंटीफ्यूज हॉल पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। यूरेनियम संवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले सेंटीफ्यूज को रखने के वारंटे बनाए गए भूमिगत स्थल को 'सेंटीफ्यूज हॉल' कहा जाता है। ये हमले इजराइल द्वारा अपने शत्रु ईरान के खिलाफ पांच दिन पहले शुरू किए गए हवाई अभियान का हिस्सा हैं, जिसमें ईरान के सैन्य और परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया गया था। यह पहली बार है जब संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने नतांज के भूमिगत हिस्से में हमलों से हुए नुकसान



भूमिगत संवर्धन हॉल पर प्रत्यक्ष प्रभाव का संकेत देते हैं। पहले ही, जमीन के ऊपर स्थित संवर्धन के लिये इस्तेमाल होने वाले क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया था, साथ ही सुविधा को संचालित करने वाले विद्युत उपकरण भी नष्ट कर दिए गए थे।

इजराइल को खुद की रक्षा का अधिकार : जी 7

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com



अल्बर्ट (कनाडा)/भाषा। कनाडा के अल्बर्ट में 51वें शिखर सम्मेलन के लिए बैठक कर रहे जी-7 नेताओं ने मंगलवार को ईरान को 'क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत' बताते हुए इजराइल के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के लोगों को तेहरान खाली करने की चेतावनी देने के बाद बैठक से स्वदेश वापस चले गए हैं। दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे जी-7 नेताओं ने ध्वजित एशिया में शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्धता दोहराई और ईरानी संकट के समाधान का आह्वान किया ताकि क्षेत्र में शत्रुता में कमी आ सके और गाजा में युद्ध विराम हो सके। 'इजराइल और ईरान के बीच हालिया घटनाक्रम' शीर्षक से जारी बयान में जी-7 नेताओं ने जोर देकर कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है और ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। नेताओं ने अपने एक संक्षिप्त

ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है। हम लगातार स्पष्ट रहे हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार नहीं हो सकते : जी 7

बयान में कहा 'हम जी-7 के नेता पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस संदर्भ में हम पुष्टि करते हैं कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हम इजराइल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि करते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का

समय में आया है जब गहराते इजराइल ईरान संकट के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति सोमवार शाम को अचानक कनाडा की अपनी यात्रा को बीच में ही छोड़ स्वदेश लौट गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी लोगों को 'तेहरान तुरंत छोड़ देने' की चेतावनी दी थी। इस बीच रवाना होने से पहले ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद से कहा 'ईरान को उस (परमाणु) समझौते पर हस्ताक्षर कर देना चाहिए था, जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। यह कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहें तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता।

18-06-2025 19-06-2025
सूर्योदय 6:47 बजे सूर्यास्त 5:54 बजे

BSE 81,583.30 (-212.85)
NSE 24,853.40 (-93.10)

सोना 10,441 ष. (24 कैरट) प्रति ग्राम
चांदी 109,016 ष. प्रति किलो

निशान मंडेला
दक्षिण भारत राष्ट्रमत
दक्षिण भारत का लोकप्रिय हिन्दी पत्रिका
epaper.dakshinbharat.com

केलाश मण्डेला, मो. 9828233434

आजादी के मायने
सेवक खुद को मालिक कहते, मालिक मजदूर बने वादी। आपना ही घर भरने के हम, हो चुके सभी इतने आदी। घट गए मूल्य विद्वानों के, हो गई आज मेंही खादी। है भेदभाव हर सिररूम में, फिर बोलो कैसी आजादी।।



मंगलवार को बेंगलूर पेलिस में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार एवं अन्य।

वन विभाग अगर अपनी जमीन पर पार्क विकसित करता है तो बीबीएमपी उसे फंड मुहैया कराएगा : डीके शिवकुमार

बेंगलूर/दक्षिण भारत । उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कहा कि अगर वन विभाग कब्ज पार्क और लालबाग की तर्ज पर बेंगलूर में वन भूमि विकसित करने के लिए आगे आता है तो बीबीएमपी उसे फंड मुहैया कराएगा। पेलिस ग्राउंड में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, अगर वन विभाग कब्ज पार्क और लालबाग की तर्ज पर अपनी जमीन पर पार्क विकसित करता है तो इससे जनता को फायदा होगा और वन भूमि पर अतिक्रमण भी नहीं होगा। हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि जमीन हमारी नहीं है बल्कि हम

मेडिकल अभ्यर्थी बिचौलियों के झांसे में न आए: पाटिल

बेंगलूर/दक्षिण भारत । कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने मंगलवार को मेडिकल सीट के दावेदार अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में बिचौलियों के झांसे में न आए। मंत्री ने आग्रह किया कि अगर ऐसे बिचौलिए अभ्यर्थी या अभिभावकों को मेडिकल सीट दिलाने के झूठे वादे करके गुमराह करते हैं तो उनकी पहचान की जाएगी और कानून के तहत उनसे कड़ाई से निपटा जाएगा। उन्होंने एक बयान में कहा कि डॉक्टर बनने के सपने के लिए कड़ी मेहनत और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को सीट हासिल करने की चिंता में धोखेबाजों के जाल में नहीं फंसना चाहिए। मंत्री ने आग्रह किया काफी लोग मेडिकल सीट दिलाने का झूठा वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि

शीर्ष अदालत के आदेश का सम्मान करेंगे : शिवकुमार

बेंगलूर। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मंगलवार को कन्नड़ कार्यकर्ताओं से उद्यम न्यायालय के आदेश का पालन करने की अपील की, जिसमें राज्य सरकार को कमल हासन अभिनेता फिल्म 'दग लाइफ' का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। अभिनेता (70) की कन्नड़ भाषा के बारे में टिप्पणी से बड़ा विवाद पैदा होने के बाद कन्नड़ कार्यकर्ता फिल्म के प्रदर्शन के खिलाफ खड़े हो गए हैं। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सिनेमाघरों को फिल्म प्रदर्शित न करने की चेतावनी दी। उनका आरोप था कि हासन ने कन्नड़ के समृद्ध इतिहास को जाने बिना उसका अपमान किया है। उद्यम न्यायालय ने 'दग लाइफ' को राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किये जाने को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और नैतिकता के तथ्यांकित पहलुओं को सड़कों पर हंगामा करने इजाजत नहीं दी जा सकती। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवकुमार ने कहा, हमें उद्यम न्यायालय के आदेश का सम्मान के साथ पालन करना होगा। हर किसी की अपनी सीमाएं होती हैं।

सहयोग दक्षिण भारत राष्ट्रमत



बेंगलूर के तैरापथ युवक परिषद राजराजेश्वरीनगर ने अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाहन करते हुए पट्टनगरे स्थित गवर्नमेंट लोअर प्राइमरी स्कूल में हनुमाननमल, संजय, मनोज बेंद आदि के सौजन्य से बच्चों के लिए डेस्क उपलब्ध करवाई गई। तैरापथ के अध्यक्ष बिकाश छाजेड़ ने सभी का स्वागत किया। स्कूल प्राध्यापक सुगना ने तैरापथ के सदस्यों को धन्यवाद दिया।



सतावीस ओसवाल जैन संघ का स्नेह मिलन सम्पन्न

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। श्री सतावीस ओसवाल जैन संघ का स्नेह मिलन देवनहली स्थित एक रिसोर्ट में रविवार को सम्पन्न हुआ। भगवान आदेश्वर के कल्याण दिवस पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। संघ के सभी सदस्यों की उपस्थिति में पदाधिकारियों ने

संघ हित में अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में संघ की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ जिसमें सर्वसम्मति से संघ के नए अध्यक्ष राजकुमार नागोत्रा सोलंकी, उपाध्यक्ष नरेशकुमार परमार, सचिव अजयकुमार नागोत्रा सोलंकी, सहसचिव गौतमचन्द्र नागोत्रा सोलंकी, कोषाध्यक्ष जयतीलाल तातेड़ सहित कार्यकारिणी सदस्यों का चयन किया गया। दोपहर में बच्चों के खेलकूद और मनोरंजक कार्यक्रम एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ही उत्साह के साथ सम्पन्न हुए। समारोह में संघ के वरिष्ठ सदस्य अमृतलाल परमार, बाबूलाल बंदामुथा, मांगीलाल जैन का सम्मान किया गया। संघ के पूर्व अध्यक्ष मांगीलाल सिरौहिया, जेमल गादिगा, शांतिलाल नागोत्रा सोलंकी, शांतिलाल कोठारी, सुरेश कुमार कोठारी एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

भगदड़ मामले में इस्तीफा मांगने वाले भाजपा नेताओं पर सिद्धरामय्या ने किया पलटवार

कहा- ऐसी घटनाओं के बाद इस्तीफा देने वाले भाजपा नेताओं की सूची जारी करें

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने चित्रारस्वामी स्टेटियम के पास हुई भगदड़ की घटना के बाद भाजपा नेताओं द्वारा उनका इस्तीफा मांगे जाने पर मंगलवार को कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मैं राज्य भाजपा के नेताओं से अनुरोध करता हूँ कि ऐसी मांग करने से पहले पूर्व में इस तरह की घटनाओं के बाद इस्तीफा देने वाले अपनी पार्टी के नेताओं की सूची जारी करें। सिद्धरामय्या ने कहा कि चित्रारस्वामी स्टेटियम के पास जो हुआ, वह एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। एक जिम्मेदार सरकार के रूप में, हमने इस घटना की जांचबदेही ली है। हमने बेंगलूर शहर के पुलिस आयुक्त सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया और राज्य खुफिया विभाग के प्रमुख का तबादला कर दिया। मेरे राजनीतिक सचिव को भी उनके कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। इसके अलावा हमने मामले की गहन जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति जॉन माइकल कुन्हा के नेतृत्व में एक सदस्यीय आयोग का गठन किया है।

सिद्धरामय्या ने कहा कि ऐसी निर्णायक कार्रवाई के बावजूद राज्य में भाजपा नेताओं की ओर से विरोध जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि उनके इरादे लोगों के प्रति वारसविक चिंता से प्रेरित होने के बजाय राजनीतिक हितों के लिए हैं।

सिद्धरामय्या ने साल 2002 के गुजरात दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने न तो पद छोड़ा और न ही आज तक कोई खेद जताया। हमारा इस्तीफा मांगने वालों को पहले इस पर ध्यान देना चाहिए। सिद्धरामय्या ने कहा कि पहलुगाम में हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी। हमारी पार्टी ने इस घटना पर प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं की थी। हमने इस पर चर्चा करने के लिए सिर्फ संसद का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया था, जिसे प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया। अभी तक इस हमले के दोषियों की पहचान नहीं हो पाई है। क्या यह केंद्र सरकार की फिलहाल नहीं है? इस विफलता के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या पं. जवाहरलाल नेहरू, राहुल गांधी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी?

अंतर-मंत्रालयी प्रयास से भारत दुर्लभ खनिज चुंबक में आत्मनिर्भर बनेगा : कुमारस्वामी

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर/नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने मंगलवार को कहा कि अंतर-मंत्रालयी प्रयास भारत को दुर्लभ खनिज चुंबक में आत्मनिर्भर बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगा। दुर्लभ खनिज चुंबक का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी), इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों, रक्षा और अन्य क्षेत्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुमारस्वामी ने यहां कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी के साथ दुर्लभ खनिज चुंबक के मुद्दे पर एक अंतर-मंत्रालयी बैठक की अध्यक्षता करने के बाद यह बात कही। कुमारस्वामी ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर लिखा कि दुर्लभ खनिज चुंबक के मुद्दे पर किशन रेड्डी के साथ हुई बैठक में

भारी उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, खान मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने कहा, यह अंतर-मंत्रालयी प्रयास ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक सामग्रियों में भारत की आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त करेगा। रेड्डी ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में चर्चा खनन से लेकर रिकार्डिंग और अंतिम उपयोग तक मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने पर केंद्रित थी। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी सरकार ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन (एनसीएमएम) को लागू किया है और खनिजों के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपना रही है। प्रमुख धातुओं के निर्यात पर चीन के हाल के प्रतिबंधों ने भारत सहित कई देशों में वाहन सहित सैमीकंडक्टर चिप के निर्माण में व्यापक गतिरोध पैदा किया है।



जेवाईएस ने होसकोटे की जीवदया गौशाला में शेड का उद्घाटन किया

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। शहर के जैन युवा संगठन (जेवाईएस) द्वारा महावीर जन्मोत्सव कार्यक्रम के दौरान फ्रीडम पार्क में गौशाला झोली में प्राण राशि व संगठन-ट्रस्ट के सदस्यों के सहयोग से होसकोटे के शांतिलाल दीपकुमार भंडारी ट्रस्ट द्वारा संचालित जीवदया गौशाला में गौशेड बनवाया गया और सहयोग राशि प्रदान की गई। संगठन के अध्यक्ष महावीर मुणोत, पूर्व अध्यक्ष भरत रांका, पूर्व उपाध्यक्ष मुकेश बाबेल, दिलीप सचेती, पूर्व सहमंत्री विपुल पोरवाल एवं सेवा ट्रस्ट के दिनेश सुराणा ने गौशाला में निर्मित गौशेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर गौशाला ट्रस्ट के अनेक पदाधिकारियों, गौशाला संचालक दीपक भंडारी, संगठन के उपाध्यक्ष मुकेश सुराणा, मंत्री नीरज कटारिया, कोषाध्यक्ष सन्तोष चौरवाल सहित अनेक सदस्य उपस्थित थे। सदस्यों ने गौशेड के बाद जय जीरावला तीर्थ, होसकोटे एवं कोलार स्थित अन्तर गंगे मंदिर के दर्शन किए।

कर्नाटक के अलीपुर गांव के 100 से अधिक लोग ईरान में फंसे

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

चिकबलपुर। इजराइल और ईरान के मध्य बढ़ते तनाव के बीच कई भारतीय नागरिक ईरान में फंसे हुए हैं। इनमें से 100 से ज्यादा लोग कर्नाटक के चिकबलपुर जिले के अलीपुर गांव से हैं। यह गांव मुख्य रूप से शिया मुस्लिमों का गांव है। इनमें छात्र, परिवार और कामकाजी पेशेवर शामिल हैं, जो शिक्षा, व्यवसाय और धार्मिक गतिविधियों के लिए ईरान गए थे। तेहरान में दूतावास और कर्नाटक में स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ भारतीय अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और क्षेत्र में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए इंतजार में सहयोग कर रहे हैं। नवीनतम मत्वादा सूची के अनुसार, अलीपुर लगभग 25,000 लोगों की आबादी वाला गांव है जिसमें 8,000 से 8,500 मत्वादा हैं। यहां हिंदुओं की आबादी भी है, लेकिन लगभग 90 प्रतिशत निवासी मुस्लिम हैं जो मुख्य रूप से शिया समुदाय से हैं। यह गांव ईरान के साथ अपने गहरे धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों के लिए जाना जाता है, जो इसे धर्म से जुड़े एवं चिकित्सा अध्ययन के लिए एक आम गंतव्य बनाता है। अलीपुर में मस्जिद-ए-जाफरिया के इमाम मौलाना सैयद मोहम्मद यूशा अबेदी ने कहा, "हमारे अलीपुर के कुछ छात्र वर्तमान में ईरान में पढ़ाई कर रहे हैं।" अबेदी ने कहा, "कोम में लगभग 50 लोग हैं और लगभग 15 छात्र तेहरान में एमबीबीएस कर रहे हैं। अन्य 25 से 30 लोग कोम और मशहद जैसे शहरों में व्यवसाय में शामिल हैं। कुल मिलाकर अलीपुर के लगभग 100 लोग वर्तमान में ईरान में हैं, जिनमें परिवार और बच्चे शामिल हैं।" हालांकि, इजराइल के हवाई हमलों के बाद ईरान के विभिन्न शहरों में रहने वाले अलीपुर के अधिकतर निवासियों को सुरक्षित क्षेत्रों में ले जाया गया है। इमाम ने कहा, भारतीय दूतावास संपर्क में है और दूतावास ने इनमें से कई को तेहरान से कोम में स्थानांतरित करने में मदद की है। ईरान में बीडीएस की छात्रा हबीबे जहरा के पिता सैयद अबू ताहिर ने कहा, वे अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हमें उम्मीद है कि सभी सुरक्षित लौट आएंगे। ताहिर ने कहा, मेरी बेटी 2024 से यहां बीडीएस की पढ़ाई कर रही है और लड़कियों के छात्रावास में रह रही है। यहां सब कुछ ठीक है, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए हम उद्विग्न हैं। हमने स्थानीय अधिकारियों को प्रस्तुत करेंगे। महाविद्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां प्रारंभिक प्रकृति की हैं और यदि उन्हें समय से पहले सार्वजनिक कर दिया गया तो मीडिया द्वारा सनसनीखेज बनाया जा सकता है। पीठ ने दोहराया कि वह स्थिति रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में रखने के प्रश्न पर विचार करेगी तथा उसने न्यायमित्र नियुक्त करने के अपने निर्णय को भी घोषणा की। इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वह इस मामले पर निर्णय लेने से पहले न्यायमित्र से सहायता लेगी। अदालत ने जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को स्पष्ट प्राथमिकता देने का संकेत दिया। महाविद्यालय ने सभी पीठों को सूचित करने के लिए 20 से 25 दिन का स्थान मांगा। हालांकि, पीठ इससे सहमत नहीं दिखी। अदालत ने पूछा, इससे हमें रुकने की क्या जरूरत है?

अदालत ने सरकार से रिपोर्ट को 'सीलबंद लिफाफे' में देने पर सवाल किया

बेंगलूर/दक्षिण भारत। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से भगदड़ पर स्थिति रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में रखने पर जोर देने के लिए सवाल किया तथा जांच प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को रेखांकित किया। यहां चित्रारस्वामी स्टेटियम के बाहर चार जून को हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। इस संबंध में स्वतःसंज्ञान याचिका जब कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी. कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सी.एम. जोशी के समक्ष सुनवाई के लिए आई, तो महाविद्यालय शशि किरण शेड्डी ने कहा कि सरकार खुलासा करने से नहीं कतरा रही है, लेकिन वह जारी जांच में पूर्णतः सतर्क नहीं है। उन्होंने राज्य द्वारा तैयार किए गए प्रारंभिक निष्कर्षों और अंततः आकलन का उल्लेख करते हुए कहा, हम अगले सप्ताह दोनों रिपोर्ट



कांठा प्रांत ट्रस्ट ने ऑनलाइन आयोजित किया कैरियर नेविगेटर कार्यक्रम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बेंगलूर। स्थानीय कांठा प्रांत जैन ट्रस्ट द्वारा भारत भर में बसे कांठा प्रांत के स्नातकोत्तर तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कैरियर नेविगेटर कार्यक्रम का आयोजन मंगलवार को किया गया जिसमें शिक्षाविद व प्रशिक्षिका डॉ. प्रतिभा जैन ने कहा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि भविष्य विषयों पर कैरियर के लिए सलाह दी जाएगी। पहले सत्र में डॉ. प्रतिभा ने नए युग के कैरियर में बढ़ते क्षेत्र

'दग लाइफ' का बहिष्कार करने की अपील करेंगे : कर्नाटक रक्षणा वेदिके

बेंगलूर/दक्षिण भारत। कन्नड़ समर्थक संगठन कर्नाटक रक्षणा वेदिके (केआरवी) ने मंगलवार को कहा कि वह लोगों से कमल हासन अभिनेता फिल्म 'दग लाइफ' का बहिष्कार करने की अपील करेंगे। केआरवी का यह बयान उद्यम न्यायालय द्वारा मंगलवार को कर्नाटक सरकार को 'दग लाइफ' का राज्य में प्रदर्शन सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाने के बाद आया है। केआरवी के प्रदेश अध्यक्ष एच शिवराम गौड़ा ने कहा, कोई भी स्वाभिमानी कन्नड़ व्यक्ति यह फिल्म क्यों देखेगा, जबकि हासन, जो न तो भाषाविद है और न ही इतिहासकार, मूर्खतापूर्ण बातें कहते हैं जो हमारी भाषा के प्रति अपमानजनक हैं।" केआरवी कन्नड़ समर्थक संगठनों में से एक है जो हासन से माफी की मांग कर रहा है। उद्यम न्यायालय के न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने बेंगलूर निवासी एम. महेश रेड्डी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हासन की फिल्म 'दग लाइफ' का प्रदर्शन सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया था। चेन्नई में 'दग लाइफ' के एक प्रमोशन कार्यक्रम में हासन ने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल से निकली है, जिसके बाद कर्नाटक में 'दग लाइफ' पर प्रतिबंध लगाने की मांग के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। गौड़ा ने कहा कि वह उद्यम न्यायालय के फैसले का सम्मान करेंगे कि फिल्मकारों और

युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कर्नाटक के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास जारी : सिद्धरामय्या

बेंगलूर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या ने मंगलवार को आश्वासन दिया कि विदेश में युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे गए राज्य के लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए प्रयास जारी हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार हालात पर करीब से नजर रख रही है और प्रभावित लोगों से संपर्क में है। सिद्धरामय्या ने यहां संवाददाताओं से कहा, "मैंने युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में फंसे कन्नड़ लोगों से बात की है।" उन्होंने कहा, "यहां हवाई अड्डे फिलहाल बंद हैं, लेकिन लोगों की उचित देखभाल की जा रही है।" मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है और स्थिति में सुधार होते ही फंसे हुए लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी। सिद्धरामय्या ने प्रभावित लोगों के परिवारों को आश्वासन देते हुए कहा, कल या परसों हवाई अड्डे के फिर से खुलने की संभावना है।



कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार मंगलवार को बंगलूर में विधान सौधा के सामने पर्यावरण दिवस समारोह के हिस्से के रूप में कर्नाटक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित मैराथन के दौरान साइकिल चलाते समय गिर गए।

ईडी ने ऐश्वर्या गौड़ा 'धोखाधड़ी' मामले में डीके सुरेश को समन भेजा

बंगलूर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के छोटे भाई और कांग्रेस नेता डीके सुरेश को एक स्थानीय महिला के खिलाफ धन शोधन की जांच से जुड़े कथित धोखाधड़ी मामले में पूछताछ के लिए समन भेजा है। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि पूर्व सांसद सुरेश को 19 जून को पेश होने और धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया है। संघीय जांच एजेंसी ने स्थानीय महिला एश्वर्या गौड़ा (33) और कांग्रेस विधायक विनय कुलकर्णी के खिलाफ छापे मारने के बाद अप्रैल में महिला को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि महिला ने कई "हार्ड-प्रोफाइल" नेताओं के साथ निकटता का दावा किया और लोगों को सोने, नकदी तथा बैंक में जमा राशि पर उच्च रिटर्न का वादा कर उनसे धोखाधड़ी की। ऐसा आरोप है कि उसने सुरेश के नाम का इस्तेमाल किया और अपने आप को उनकी बहन बताया। सुरेश ने बंगलूर पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि उनके नाम का "दुरुपयोग" किया जा रहा है।



भाजपा द्वारा विरोध प्रदर्शन विजयेंद्र येडीयुरप्पा, आर. अशोक, चलवाडी नारायणस्वामी और अन्य प्रमुख नेता गिरफ्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बंगलूर। उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर बंगलूर के फ्रीडम पार्क में विशाल विरोध प्रदर्शन करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान विधानसभा स्टेडियम के पास भगवद में 11 निर्दोष लोगों की मौत से निपटने में राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलता के कारण भाजपा ने उपमुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्रियों और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए विशाल विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया।

यह विरोध प्रदर्शन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक विजयेंद्र येडीयुरप्पा, विपक्ष के नेता आर. अशोक, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन में विधानसभा में विपक्ष के मुख्य सचेतक दोड्डनगौड़ा एच. पटिल, राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. सी.एन. अश्वथनारायण, पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद गोविंदा कारजोल, सांसद पी.सी. मोहन, विधान परिषद विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रविकुमार, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक शैली बसवराज, पूर्व मंत्री और विधायक के. गोपालैया, विधायक एल. रविशुब्रमण्यम, उदय गरुडवार, एस. मुनिराजु, एम. कृष्णाप्पा, विधान परिषद सदस्य केशव प्रसाद, भारतीय शैली, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक धीरज मुनिराजु, बंगलूर दक्षिण जिला अध्यक्ष और विधायक सी.के. राममूर्ति, बंगलूर उत्तर जिला अध्यक्ष एस. हरीश, बंगलूर मध्य जिला अध्यक्ष सगिरी गौड़ा, राज्य पदाधिकारी और पार्टी नेता, कार्यकर्ता शामिल हुए।

कर्नाटक 'टग लाइफ' की रिलीज सुनिश्चित करे मीड को सड़कों पर कब्जे की अनुमति नहीं दी जा सकती : न्यायालय

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बंगलूर/नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने अभिनेता कमल हासन की फिल्म 'टग लाइफ' को राज्य के सिनेमाघरों में प्रदर्शित नहीं किये जाने को लेकर कर्नाटक सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भीड़ और नैतिकता के तथ्यांकित पहलुओं को सड़कों पर हंगामा करने इजाजत नहीं दी जा सकती। न्यायमूर्ति उजल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि कानून का शासन स्थापित किया जाना चाहिए और लोगों को फिल्म देखने से रोकने के लिए उनके सिर पर बंदूक नहीं लानी जा सकती। न्यायमूर्ति भुइयां ने कर्नाटक सरकार के वकील से कहा, हम भीड़ और नैतिकता के तथ्यांकित पहलुओं को सड़कों पर कब्जा करने की इजाजत नहीं दे सकते। कानून का शासन कायम रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। अगर किसी ने कोई बयान दिया है, तो उसका जवाब बयान से दीजिए। अगर किसी ने कुछ लिखा है, तो आप उसका जवाब कुछ लिखकर दे सकते हैं। उन्होंने वकील को 18 जून तक मामले पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि भले ही फिल्म प्रदर्शित होने पर लोग इसे न देखें, लेकिन उन्हें इस डर में नहीं रखा जा सकता कि सिनेमाघर जला दिए जाएं।

कर्नाटक में फिल्म प्रदर्शित न किए जाने को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता एम महेश रेड्डी की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ए. वेलम ने कहा कि राज्य ने धमकी देने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं की है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, कानून के शासन के मुताबिक, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) से प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुकी कोई भी फिल्म अवश्य रिलीज होनी चाहिए और राज्य को इसकी रीविजिंग सुनिश्चित करनी चाहिए। आप लोगों के सिर पर बंदूक रखकर यह नहीं कह सकते कि फिल्म मत देखो।

न्यायाधीश ने आगे कहा, "ऐसा नहीं हो सकता कि सिनेमाघरों को जलाए जाने के डर से फिल्म न दिखाई जाए। लोग फिल्म न देखें। यह एक अलग मामला है। हम ऐसा कोई आदेश नहीं दे रहे हैं कि लोगों को फिल्म देखनी चाहिए। लेकिन फिल्म रिलीज होनी चाहिए।" कर्नाटक का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील ने कहा कि फिल्म निर्माता द्वारा दायर याचिका पर 20 जून को उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। इसके बाद पीठ ने उच्च न्यायालय में लिखित याचिका को उच्चतम न्यायालय में स्थानांतरित करने का संकेत दिया। शीर्ष अदालत ने 3 जून को उच्च न्यायालय द्वारा की गई उन टिप्पणियों की भी आलोचना की, जिसमें कमल हासन से उस बयान के लिए माफी मांगने को कहा गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि "कन्नड भाषा का जन्म तमिल भाषा से हुआ है।" न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा "उनसे (हासन से) माफी के लिए कहना उच्च न्यायालय का काम नहीं है।"

न्यायाधीश ने कहा, "यह मुझ कानून के शासन और मौलिक अधिकारों से जुड़ा है। इसलिए, यह न्यायालय हरतक्षेप कर रहा है। उच्चतम न्यायालय का उद्देश्य कानून के शासन और मौलिक अधिकारों का संरक्षण होना है। यह केवल एक फिल्म के बारे में नहीं है।" पीठ ने कहा कि यदि कमल हासन ने कुछ भी अभियोग कहा है, तो उसे अदालत सत्य नहीं माना जा सकता और कर्नाटक के प्रमुख लोगों को इस पर बहस करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि वह गलत है। न्यायमूर्ति मनमोहन ने कहा, "यह एक बयान देना है और उसे अंतिम सत्य मान लिया जाता है। इस मुद्दे पर बहस होनी चाहिए। लोगों को कहना चाहिए कि वह गलत है।"

न्यायमूर्ति भुइयां ने कहा, "बंगलूर के सभी प्रमुख लोग बयान जारी कर सकते हैं कि वह (हासन) गलत है। धमकियों का सहारा क्यों लिया जाना चाहिए?" कानून के शासन के महत्व को रेखांकित करते हुए, पीठ ने राज्य पर फिल्म की रिलीज सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डाल दी।

क्र. सं. एसके-22011/10/2025-कोथल
भारत सरकार / Government of India
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
Ministry of Social Justice & Empowerment
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

5वां बल, बी. विंग, पी. देन्दयाल अंत्योदय भवन, सीजी कॉम्प्लेक्स, सीपी रोड, नई दिल्ली-110003
5th Floor, B Wing, P. Deendayal Antyodaya Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110003

दिव्यांग छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग अपने राष्ट्रीय संस्थानों (एनआई) समेकित क्षेत्रीय केन्द्रों (सीआरसी) और पैनालबेड केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही 'दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना' के तहत निःशुल्क कोचिंग का लाभ उठाने के लिए बेंचमार्क दिव्यांगता यानी 40 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले पात्र दिव्यांग छात्रों से आवेदन आमंत्रित करता है।

- इस पहले के उद्देश्य 8.00 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों के छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने तथा उन्हें व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए सशक्त बनाना है।
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता इस प्रकार है।

क्रम सं.	विवरण	राशि
1.	निःशुल्क कोचिंग	40,000 रु/- - 75,000 रु/- (पाठ्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार)
2.	वजीफा (स्टाइपेंड)/रखरखाव भत्ता	4,000 रु/- प्रतिमाह
3.	दिव्यांगता भत्ता	2,000 रु/- प्रतिमाह
4.	पुस्तक भत्ता	5,000 रु/- (एक बारगी प्रति पाठ्यक्रम)

4. पात्रता, अनुमोदित पाठ्यक्रमों, कार्यान्वयन एजेंसियों तथा योजना के दिशा निर्देशों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट <https://depwd.gov.in/scholarship/> देखें। इससे संबंधित अधिक जानकारी या प्रश्नों के समाधान के लिए, आप ds.skillnap-depwd@gov.in के माध्यम से या टेलीफोन नम्बर 011-24369025 पर हमसे सम्पर्क कर सकते हैं।

अवर सचिव, भारत सरकार
CBC 38117/11/0004/2526

भारत सरकार, अंतरिक्ष विभाग
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
(निर्माण एवं अनुसंधान प्रभाग)
इसरो टेलिमेट्रि टैकिंग एवं कमांड नेटवर्क (इस्ट्रेक)
प्लॉट नं. 12 एवं 13, तीरुवा मेन, द्वितीय फेज,
पीपुला औद्योगिक क्षेत्र, बंगलूर-560058
फोन : 080-28094182, 4541 फैक्स : 080-28094180

संघोचन-1 दिनांक 17.06.2025

भारत के राष्ट्रपति की ओर से, समुचित वर्ग के उम्मीदवारों से निम्नलिखित कार्यों के लिए नग वर ई-निविदाएं ऑनलाइन आमंत्रित की जाती हैं।

एनआईटी सं.	इस्ट्रेक/सीएमजी/ई/एम/आईएनटी/ईटीएन-26 / 2025-26 दिनांक 29.05.2025
कार्य का नाम	इसरो हाउसिंग कॉलोनी, आरपीसी लेआउट और अंतरिक्ष अपार्टमेंट, मड्डेबेरम, इस्ट्रेक, बंगलूर में 1सी ब्लॉक, 2सी ब्लॉक, 3सी ब्लॉक और बी-ब्लॉक में कॉमन एरिया लाइटिंग, लिफ्ट रूम लाइटिंग सर्किट के नवीनीकरण के लिए विद्युत कार्य।
निविदा का अनुमानित मूल्य	रु. 14.84 लाख
निविदा दर्तावेज	ई-निविदा
विवरण	कार्य समापन अवधि
	02 (दो) माह
निविदा प्रलेख डाउनलोड करने की अवधि	30.05.2025 को 16.00 बजे से 12.06.2025 को 16.00 तक। 25.06.2025 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
बोली स्पष्टीकरण	31.05.2025 को 11.00 बजे से 13.06.2025 को 16.00 तक। 26.06.2025 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
बोली स्पष्टीकरण के जवाब देने की अंतिम तारीख	14.06.2025 को 16.00 तक। 27.06.2025 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
निविदा प्राप्ति की अंतिम तारीख और समय	15.06.2025 को 16.00 तक। 28.06.2025 को 16.00 बजे तक बढ़ाया गया है।
निविदा खोलने की नियत तारीख और समय	17.06.2025 को 11.00 से, 30.06.2025 को 16.00 बजे से, तक बढ़ाया गया है।
अग्रदाय रकम जमा (ईएमडी)	रु. 29,680.00

पात्रता मानदंड और अन्य व्योरे के लिए इष्टक निविदाकार विस्तृत सूचना आमंत्रण निविदा (एनआईटी) देखें जिसे वेबसाइट www.isro.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। बोली प्रपत्र और अन्य व्योरे वेबसाइट www.tenderwizard.com/ISRO से डाउनलोड किए जा सकते हैं।
ह/- समूह प्रमुख- सीएमजी

कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति करने की कला में माहिर है : रवि कुमार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत dakshinbharat.com

बंगलूर। भाजपा ने मंगलवार को उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी लाशों पर राजनीति करने की कला में माहिर है। कर्नाटक विधान परिषद में विपक्ष के मुख्य सचेतक एन. रवि कुमार ने यहां जारी एक बयान में कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1985 और 1991 के संसदीय चुनावों में किस तरह से वोट मांगे और सहानुभूति लहर के आधार पर जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय त्रासदियों के कारण उन चुनावों में सफल रही। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वह भावनाओं को भड़का कर जीत हासिल करती रही है। झड़ुअपनी ही पार्टी में उपमुख्यमंत्री की कमजोर स्थिति है। रवि कुमार ने कहा कि अगर वह इस मुद्दे पर चुप रहते हैं तो उनके लिए अच्छा होगा। रवि कुमार के अनुसार, राज्य सरकार ने खुद को इस भीषण त्रासदी के लिए दोषी ठहराने से बचाने के लिए पुलिस अधिकारियों पर दोष मढ़ने की कोशिश की है। पहले मुख्यमंत्री सिद्दहामय्या ने कहा कि राज्य सरकार ने विधान सौधा की भयंकर आगोष्ठी नहीं किया था। जब राजभवन से स्पष्टीकरण आया कि मुख्यमंत्री ने वास्तव में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए राज्यपाल को बुलाया था, तो सिद्दहामय्या ने घुटन लिया और कहा कि उन्होंने वास्तव में राज्यपाल को आमंत्रित किया था। यह स्पष्ट है कि राज्य सरकार पुलिस अधिकारियों के साथ-साथ आरसीबी और केएससीए को दोषी ठहराकर किसी न किसी तरह से संकेत से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। केएससीए के आयोजन में कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य था, हालांकि कार्यक्रम आरसीबी और केएससीए द्वारा आयोजित किया गया था। इस भयावह त्रासदी में राज्य सरकार हर तरह से गलत है। रवि कुमार ने कहा, भाजपा द्वारा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग करना सही है।

महिला ने शराबत करने पर बेटे को गरम छड़ से दागा, हिरासत में ली गई

हुबली। कर्नाटक के हुबली शहर में एक मां को अपने बेटे को गर्म लोहे की छड़ से जलाने के आरोप में पुलिस ने हिरासत में लिया है। महिला ने कथित रूप से बेटे के शराबती व्यवहार से नाराज होकर यह क्रूर सजा दी। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अनुषा हुल्लिमारा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को पुराने हुबली के टीपू नगर में हुई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अनुषा अपने बेटे के व्यवहार से गुस्से में आ गईं और उसने गर्म लोहे की छड़ से बच्चे के हाथ, पैर और गर्दन को जला दिया। बच्चे की चीख-पुकार सुनकर पड़ोसी मोके पर पहुंचे और बच्चे को उसकी मां से बचाया। स्थानीय लोगों ने इस अमानवीय कृत्य को देखकर तुरंत पुलिस को सूचना दी।

सार्वजनिक नोटिस

मेसर्स टेक ग्रोन एव एम. प्रोवैट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय दूसरी मंजिल, स्वयंवर वन मात, सफेक विननेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चौक पुष्प विहार नई दिल्ली-110017, भारत सरकार को विद्युत अभियान, 2003 की धारा 164 के तहत विद्युत लाइनों अथवा विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिये अथवा टेलीफोन या टेलीग्राफिक संवाहक के उद्देश्य से कच्चे के उचित समय के लिये आवश्यक वे सभी शक्तियां प्रदान करने के लिये आवेदन करने की इच्छुक है, जो टेलीग्राफ प्रधिकरण द्वारा भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के तहत सरकार द्वारा स्थापित किए गये या बनाए गये या स्थापित किये जाने वाले या बनाये जाने वाले टेलीग्राफ के उद्देश्य से टेलीग्राफ लाइनों और पोस्टों की स्थापना के संबंध में धारित हैं और निम्न लिखित पारंपरिक योजना के लिए संबंधित, निर्माण, संस्थापन, निरीक्षण, उन्नाहन और अन्य कार्य के पश्चात प्रत्यानयन, प्रभावान, अनुरक्षण करेगी:

ट्रांसमिशन योजना का नाम: प्रस्तावित 220 केवी डी/सी टावर और एस/सी लाइन हुबली कन्वेंटिविटी सिस्टम, पीएसएस-2 गुड्डलह गंव से पीएसएस-1 मागलतिरिनी, मुद्देबिहाल तालुका, विनयपुरा जिला तक और पीएसएस-2 से प्रस्तावित 400/220 केवी रीट्रोफिटिंग स्टेशन (पीसीसीआईएफ) के पास कोरवार गंव, तालिकोटी तालुका, विनयपुरा जिला तक प्रस्तावित 220 केवी डी/सी लाइन।

योजना के तहत कर की गई ट्रांसमिशन लाइन: टेक ग्रोन एव एम. प्रोवैट लिमिटेड जनरेटर युक्ति स्टेशन 220 केवी डी/सी टावर और एस/सी लाइन प्रस्तावित वे, पीएसएस-2 गुड्डलह गंव से पीएसएस-1 मागलतिरिनी, मुद्देबिहाल तालुका, विनयपुरा जिला तक और पीएसएस-2 से प्रस्तावित 400/220 केवी रीट्रोफिटिंग स्टेशन (पीसीसीआईएफ) के पास कोरवार गंव, तालिकोटी तालुका, विनयपुरा जिला तक प्रस्तावित 220 केवी डी/सी टावर और एस/सी लाइन कोरवार गंव के पास, तालिकोटी तालुका, विनयपुरा जिला तक। लाइन की लंबाई लगभग 55 किमी है। कोरवार गंव, तालिकोटी तालुका, जिला- विनयपुरा के निकट से 2 किमी (लगभग) लाइन को एम/सी टावरों पर एस/सी लाइन के रूप में क्रियान्वित की जाएगी।

उपरोक्त योजना के तहत कर की गई ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन निम्नलिखित गांवों, कस्बों और शहरों के ऊपर, आस-पास और बीच से होकर गुजरेगी।

जिला	तालुका	गांवों के नाम
विनयपुरा	मुद्देबिहाल	तननाल (तारानाल), चौडी, जंग मुरल (जंगमुराल), बुदिहाल (बुदिहाल), अंबावाह (अंबावाहा), कुत्तोगी, हीरमुरल (हीर मुराल), अरे मुरल (अरेमुराल) कर्बोडगुडी (कावडिमडी), होकरनी, मुद्देबिहाल (मुद्देबिहाल), कर्बोडगुडी (कर्बोडगुडी), जलपुर (जलपुर), बालवट (बालवट), मडिके सिरेर (मडिके सिरेर), चक्कनी (चक्कनी), इलांगेरी (इलांगेरी), अम्बालिनी (अम्बालिनी), मल्लपुर, मागलतिरिनी (मागलतिरिनी), नागलाली, हल्लूर (हल्लूर), हुगलवा (हुगलवा), बनावल्ली (बनावल्ली)
विनयपुरा	तालिकोटी	पेरुन्नूर (पेरुन्नूर), केन्नूर (केन्नूर), सोमना (सोमना)
विनयपुरा	वसवन कर्बोडगुडी (वसवन कर्बोडगुडी)	वडुवडगी, नंदीहाल (नंदीहाल), हुडुवेडी (हुडुवेडी), नागलालहुडी (नागलाल हुडी), सिंदेगरी (सिन्धेगरी)
विनयपुरा	वेरा शिपारगी	कडुकी (कडुकी), पाववर (पाववर), कोरवार (कोरवार), बुदिहाल (बुदिहाल) कोडगुडी (कोडगुडी), बरकनली, शिपारगी, नागलाल (नागलाल होनी), मेरवावणी (मेरवावणी), जलज (जलज), इलांगेरी (इलांगेरी), मुल्लूर
विनयपुरा	विनयपुरा	मेनल (मेनल)

एन. रवि कुमार को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि के दो आठ के भीतर प्रस्तावित पारंपरिक प्रस्तावों के संबंध में टिप्पणी/प्रतिक्रिया लिखित रूप में अग्रोवसारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जाता है।

अधिक जानकारी और स्पष्टीकरण के लिए कृपया संपर्क करें। नाम - विनयपुरा सिंह, पद कीर्ति (ट्रांसमिशन), टेक ग्रोन एव एम. प्रोवैट लिमिटेड, दूसरी मंजिल, स्वयंवर वन मात, सफेक विननेस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चौक, पुष्प विहार, नई दिल्ली-110017 भारत, ईमेल- vinet.singh@2025power.in, फोन - 8744000834



विधानसभा के समापति यू.टी. खादर फरीद अध्ययन के लिए मलेशिया पहुंचे

बंगलूर। कर्नाटक विधानसभा के सभापति और कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, कर्नाटक शाखा के संयुक्त अध्यक्ष यू.टी. खादर फरीद, जो मलेशिया में अध्ययन दौर पर हैं, ने मंगलवार को कुआलालंपुर में संसद भवन में प्रतिनिधि सभा (दीवान राकयत) के स्पीकर और कॉमनवेल्थ संसदीय संघ, मलेशिया के संयुक्त अध्यक्ष डॉ. जोहरी बिन अब्दुल से मुलाकात की।

इस अवसर पर स्पीकर खादर फरीद ने संसदीय मामलों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर विचारों का आदान-प्रदान किया। उन्होंने कर्नाटक और मलेशिया के बीच राजनीतिक, संसदीय मामलों और सांस्कृतिक संबंधों के भविष्य पर भी चर्चा की।

सी-डैक CDAC

प्रवेश अधिसूचना
सी-डैक एडवांस्ड सर्टिफिकेशन कोर्स
हार्ड परफॉरमेंस कंप्यूटिंग और इसके अनुप्रयोग

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

हाइलाइट

- अवधि: 6 महीने
- मोड: ऑफलाइन
- कोई पंजीकरण शुल्क नहीं
- पाठ्यक्रम शुल्क: Rs. 1,75,000 मुफ्त

फ्रायदे

- उद्योग विशेषज्ञ मार्गदर्शन
- सी-डैक विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन
- केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिलाओं को ₹10,000/- की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी।
- नवीनतम प्रौद्योगिकी पर व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र

आवेदन करने की अंतिम तिथि
June 26, 2025

c-huk@cdac.in <https://c-huk.cdacb.in>

सुविचार

प्रेम का असली मतलब राधा-कृष्ण से पूछो, जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ बस महसूस किया जाता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

इजराइल के निशाने पर कौन ?

ईरान और इजराइल के बीच सैन्य संघर्ष खतरनाक मोड़ पर आ पहुंचा है। दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक ईरान को ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी मारे गए हैं। इजराइल का पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड रहा है कि वह अपने दुश्मन के शीर्ष नेतृत्व पर न सिर्फ हमला करता है, बल्कि उसका खाल्ना करने से भी नहीं हिचकता। उसने हमला, हिज्रुला के शीर्ष कमांडरों का सफाया कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है— क्या अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई उसके निशाने पर हैं? हालांकि ऐसी खबरें हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल की इस योजना को वीटो कर दिया है। क्या जंग की आग ज्यादा फैलने की सूरत में भी इजराइल ट्रंप का आदेश मानेगा? अभी उसका पलड़ा भारी है, लेकिन ईरान के पास मिसाइलों का भारी जखीरा है। वह तेल अवीव समेत कई इलाकों पर हमले कर चुका है, जिससे इजराइली नागरिकों में अफरा-तफरी मची है। अगर इस टकराव के दौरान इजराइल को कोई बड़ा नुकसान हुआ या संघर्ष लंबा खिंचा तो प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान के सर्वोच्च नेता पर हमला करने का आदेश देने से गुरेज नहीं करेंगे। वे इसके स्पष्ट संकेत दे चुके हैं। अगर इजराइल किसी तरह खामेनेई तक 'पहुंचने' में कामयाब रहा तो ईरान में अराजकता फैल सकती है। वहां आईआरजीसी और अन्य कट्टरपंथी समूह सत्ता पर कब्जा कर सकते हैं। यही नहीं, वे ईरान की जनता से सहानुभूति लेते हुए इजराइल पर हवाई हमले तेज कर सकते हैं। इससे मध्य पूर्व में भारी उथल-पुथल मच सकती है।

खामेनेई के जाने से ईरान की राजनीति में एक खालीपन पैदा हो सकता है। उसे भरने के लिए उनके बेटे या किसी अन्य मजहबी नेता को आगे लाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में जितना समय लगेगा, इजराइल उसका फायदा उठाना चाहेगा। नेतन्याहू ईरान की जनता से पहले ही यह अपील कर चुके हैं कि 'दुष्ट और दमनकारी' शासन से अपनी आजादी के लिए खड़े हों। अगर ईरान की राजनीति में खालीपन पैदा होगा तो अमेरिका और इजराइल ऐसे संगठनों को समर्थन दे सकते हैं, जो 'बदलाव' के लिए आवाज बुलंद करें। याद करें, महसा अमीनी के साथ बर्बरता होने के बाद पूरे ईरान में खामेनेई के खिलाफ नारे गूँजने लगे थे। उस आंदोलन को बुढ़ी तरह कुचला गया और सैकड़ों महिलाओं की मौत हुई थी। क्या उनके परिजन (खामेनेई के न रहने पर) दोबारा उसी व्यवस्था का समर्थन करेंगे, जो कट्टरपंथी रवैया अपनाए और महिलाओं पर सख्त पाबंदियां थोपे? ट्रंप और नेतन्याहू जानते हैं कि ईरान में ऐसे लोगों की अच्छी-खासी तादाद है, जो खामेनेई की नीतियों को पसंद नहीं करते और चाहते हैं कि देश में बदलाव आए। अमेरिका-इजराइल इस वर्ग के कुछ चर्चित चेहरों को आगे लाकर उन्हें सत्ता और व्यवस्था परिवर्तन का पैरोकार बना सकते हैं। इससे ईरानी समाज बंट जाएगा और कट्टरपंथी खेमे की पकड़ कमजोर होगी। हालांकि यह इतना आसान नहीं होगा। अगर इजराइल की काफी कोशिशों के बावजूद खामेनेई सुरक्षित रहे तो ईरान में उनकी स्थिति बहुत मजबूत हो सकती है। कट्टरपंथी समूह उन्हें किसी महानायक की तरह मानेंगे। इससे ईरान की आक्रामकता में और धार आएगी तथा इजराइल पर ज्यादा घातक हमले होंगे। ईरानी प्रॉक्सि समूह ज्यादा जोश के साथ मैदान में उतरेंगे और इजराइल के लिए चुनौतियां पैदा करेंगे। भविष्य में जो भी स्थिति पैदा हो, इतना तय है कि अगर सैन्य संघर्ष जल्दी नहीं रुका तो दोनों ही तरफ जान-माल का नुकसान बढ़ता जाएगा। ईरान को शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के नाम पर अपने खतरनाक मंसूबे से पीछे हटना होगा। इसे इजराइल अपने अस्तित्व के लिए खतरा मानता है। अगर ईरान असल में शांति चाहता है तो उसे अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की निगरानी में ही परमाणु कार्यक्रम की अनुमति मिलनी चाहिए।

ट्वीटर टॉक



विश्व मरुस्थलीकरण से सूखा रोकथाम विवरण पर आफरी में आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में माननीय केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव के साथ प्रतिभाग किया। इसमें ईको सिस्टम के सुधार को प्राथमिकता देती उद्देश्यपरक चर्चा हुई।

-गजेन्द्र सिंह शेखावत

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व आज मुख्यमंत्री निवास पर विद्यार्थियों एवं सुरक्षाकर्मियों के साथ योगाभ्यास किया। सभी प्रदेशवासियों से आग्रह है कि योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं और 'स्वस्थ, समृद्ध व विकसित राजस्थान' के निर्माण में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें।

-भजनलाल शर्मा



संसदीय क्षेत्र बूंदी में केन्द्रीय विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों से संवाद का अवसर मिला। यह विद्यालय परिसर शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, तकनीकी दक्षता और राष्ट्रीय चेतना का संगम बने, यही हमारी अपेक्षा है।

-ओम बिरला

प्रेरक प्रसंग

जीवन की लय

एक बार चीनी संत चुआंग तेजु की पत्नी कुछ दिनों से अस्वस्थ थीं। अंततः उनका निधन हो गया। परंतु जब चुआंग तेजु ने उन्हें मृत देखा तो उन्होंने पल भर के लिए भी कोई शोक नहीं किया। इसके विपरीत, वे अपनी कुरिया के बाहर बैठकर चाय पत्र बजाने लगे और गाने लगे। यह दृश्य देखकर लोग चकित रह गए। जब यह समाचार चीन के सम्राट तक पहुंचा, तो वे स्वयं उन्हें सांत्वना देने वहां पहुंचे। लेकिन वहां का दृश्य देखकर सम्राट रतख रह गए। उन्होंने चुआंग तेजु से पूछा, 'तुमने तो हद कर दी! कम से कम इस शोक की घड़ी में मौन तो रह सकते थे। गाना-बजाना तो बिल्कुल अनुचित है!' चुआंग तेजु मुस्कुराते हुए उत्तर देने लगे, 'मैं क्यों रोऊं? क्या गमगीन हो जाऊं? मैं तो पहले से ही जानता था कि यह सदा जीवित नहीं रहेगी। यह शरीर तो नश्वर है। जब वह थी, तब हमने प्रेम और संगीत से जीवन जिया। अब जब वह नहीं रही, तो मैं उसे विदाई भी उसी प्रेम, शांति और संगीत के साथ क्यों न दूँ?' संत चुआंग तेजु जीवन भर यही सिखाते रहे कि जीवन गतिशील है, इसकी को किसी भी परिस्थिति में टूटने न दो।

सामयिक

प्रधानमंत्री मोदी की साइप्रस यात्रा के मायने

चेतनादित्य आलोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस, कनाडा और क्रोएशिया की अपनी अत्यंत महत्वपूर्ण यात्रा के पहले चरण में यूरोपीय संघ के सदस्य देश साइप्रस पहुंचे, जो भारत का पुराना मित्र भी है। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस ने हवाई अड्डे पर पहुंचकर उनका जोरदार स्वागत किया। बाद में, उन्होंने पीएम मोदी को वहां के सर्वोच्च सम्मान से अलंकृत भी किया, जो भारत और साइप्रस के प्रगाढ़ हो रहे संबंधों को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत के वैश्विक संबंधों को मजबूत करना, आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना तथा वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) की प्राथमिकताओं को लेकर कूटनीतिक प्रयासों को और तेज करना है। देखा जाए तो उपर्युक्त तीन देशों में भी साइप्रस का भारत के लिए अत्यंत विशेष महत्व है। हालांकि, अब तक हमने इस ओर कम ही ध्यान दिया है। तभी तो, लगभग 22 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने साइप्रस का आधिकारिक दौरा किया है। इससे पहले 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने और 2002 में प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की आधिकारिक यात्रा की थी। बहरहाल, पीएम मोदी के साइप्रस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में आई मधुरता, एकजुटता और आपसी सहयोग की भावना आने वाले समय में तुर्की की नींद हलक करने वाली साबित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

दरअसल, प्रधानमंत्री मोदी के इस दौर के उद्देश्य केवल भारत और साइप्रस के बीच मित्रता को बढ़ाना नहीं, बल्कि भारत के खिलाफ विशेषकर कश्मीर के मुद्दे पर खुलकर बोलते रहने वाले एवं पाकिस्तान को सैन्य तथा कूटनीतिक समर्थन और सहयोग प्रदान करते रहने वाले साइप्रस के पड़ोसी तुर्की को सख्त संदेश देना



भी है कि भारत उसकी हरकतों का जवाब देना अच्छी तरह से जानता है। वहीं, भारत का साइप्रस के साथ खड़े होना तुर्की के लिए साफ संदेश है कि भारत उसके खिलाफ उन देशों का समर्थन कर करता रहेगा, जो तुर्की की आक्रामकता से परेशान हैं। तात्पर्य यह कि भारत ने तुर्की की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। साथ ही, पीएम मोदी की इस यात्रा से यह उम्मीद भी जगी है कि यह दोनों देशों के बीच की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के अलावा आपसी व्यापार, संस्कृति एवं रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने में भी प्रभावी साबित होगा। यह उम्मीद निराधार भी नहीं है, क्योंकि साइप्रस की भौगोलिक स्थिति इसे भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण बनाती है। बता दें कि यह भूमध्य सागर में तुर्की के दक्षिण में, लेवांत (सीरिया-लेबनान-फिलिस्तीन-इजरायल) के पश्चिम में और स्वेज नहर के निकट स्थित है। यानी साइप्रस यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव है, जो भारत-मध्य-पूर्व-यूरोप कॉरिडोर (आइएमपीसी) के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो सकता है।

आइएमपीसी एक ऐसा व्यापारिक कॉरिडोर अथवा रास्ता है, जो भारत को मध्य-पूर्व के रास्ते यूरोप से जोड़ सकता है। यदि साइप्रस को इस कॉरिडोर में शामिल कर लिया जाए तो न केवल व्यापारिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने, बल्कि

तुर्की की अनपेक्षित हेकड़ी को बंद करने में भी सफलता मिल सकती है। दरअसल, इसी उद्देश्य से भारत ने हाल के वर्षों में तुर्की के तमाम विरोधी देशों, जिनमें ग्रीस, आर्मेनिया, मिस्र और साइप्रस के साथ अपने संबंधों को मजबूती प्रदान करने के प्रयास किए हैं। इस क्रम में ग्रीस, आर्मेनिया, और मिस्र के साथ मित्रता एवं व्यापारिक तथा सामरिक संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से पीएम मोदी उन देशों के दौरे पहले ही कर चुके हैं। अब, उनकी यह साइप्रस यात्रा तुर्की को चारों तरफ से घेरने के भारत के रणनीतिक अभियान का ही एक हिस्सा प्रतीत होती है। वैसे, भारत के लिए साइप्रस की मित्रता हमेशा से बेहद महत्वपूर्ण रही है। बता दें कि संकट काल में साइप्रस ने हमेशा भारत का साथ दिया है, चाहे 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद का समय हो, जब हम दुनिया में अलग-थलग पड़ने लगे थे या 2008 में भारत-अमेरिका परमाणु समझौते के समय अथवा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए वैश्विक समर्थन जुटाने का मामला हो। इसके अतिरिक्त, आतंकवाद और कश्मीर जैसे मुद्दों पर भी साइप्रस ने पाकिस्तान या तुर्की के बजाए हमेशा भारत का साथ दिया है।

वहीं, भारत भी हमेशा से साइप्रस की एकता और अखंडता का समर्थन करता रहा है, बल्कि

मंथन

डॉ. एस.डी. वैष्णव

मध्य-पूर्व में युद्ध की विभीषिका के बीच यह चर्चा आम है कि इजरायल जैसा छोटा-सा देश जो मुस्लिम देशों से घिरा होने के बावजूद, ईरान जैसे ताकतवर मुस्लिम राष्ट्र से युद्ध भूमि में दो-दो हाथ कैसे कर पा रहा है? ईरान के प्रॉक्सि संगठनों- हमला, हिज्रुलाह और हत्ती विद्रोहियों को बैकफुट पर धकेलकर अब सीधे ईरान में बारूदी कोहराम मचा रहा है। यह कैसे संभव हो पा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में इसके चार कारण सीधे-सीधे नजर आते हैं- पहल में अमरीका, खुफिया एजेंसी मोसाद, इजरायल डिफेंस फोर्स और उनका मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम। लेकिन, इनके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण कारण और है। यह भले ही युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं है, लेकिन उसके दश ने यहूदियों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए फोलाद के समान मजबूत और साहसी बना दिया और वह है- 'होलोकॉस्ट'।

वर्ष 1940 के दशक में यूरोपीय यहूदियों का नरसंहार हुआ, जिसे होलोकॉस्ट के रूप में जाना जाता है। जर्मनी में 1933-45 तक तानाशाह शासक एडोल्फ हिटलर का शासन रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाज़ी जर्मन और उसके सहयोगियों

अतीत में मिले नाज़ी दंश को कमी नहीं मूलते यहूदी

द्वारा 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया गया। इतिहास में यह एक ऐसी त्रासदी थी; जिसमें यहूदियों का ही नहीं, सोवियत बंदी, पोलिश तथा सोवियत नागरिकों का भी कत्लेआम हुआ। उस वक्त हिटलर के खोफ के कारण पोलैंड से कई नागरिक समुद्री मार्ग से भागकर युजुरात के जामनगर तट पहुंचे, जहाँ उन्हें तत्कालीन महाराजा दिव्यजय सिंह ने जिन्हें हम जाम साहिब के नाम से भी जानते हैं, वर्षों तक अपने यहाँ शरण दी। यही कारण है कि आज पोलैंड में जाम साहिब का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। हिटलर के शासनकाल में यूरोप में नाज़ी विचारधारा ने यहूदियों की आर्थोपिका छीन ली, उनके घर और प्रार्थना स्थल नष्ट करके उन्हें यतना शिविरों में कैद कर दिया गया। सितंबर 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण ने यहूदियों के उर्पीड़न के साथ एक नई चरमपंथी सोच को भी जन्म दिया। यूरोपीय यहूदियों पर हुए अत्याचारों का जीवंत

और रुह कंया देने वाला चित्रण ऐनी फ्रैंक की डायरी में देखने मिलता है; जिसमें उसने एम्स्टर्डम में प्रिंसेमाच पर स्थित एक गुप्त एनेक्स यानी 'छिपा हुआ कमरा' का उल्लेख किया है, जहाँ होलोकॉस्ट की शिकार ऐनी अपने परिवार के साथ एक बंदी के रूप में अपनी रातें गुजारते हुए, नाज़ी अत्याचारों की पराकाष्ठा को अपनी डायरी में शब्दबद्ध करती है। द्वितीय विश्व युद्ध मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध है, तो यहूदियों के लिए काला अध्याय भी। लाखों यहूदी मार दिए गए और जो बचे, उन्हें विस्थापन का दर्श झेलना पड़ा। होलोकॉस्ट के लिए हिब्रू भाषा में 'शोआद' शब्द का जिक्र होता है, जो समग्र विनाश या आपदा के प्रतीकात्मक रूप में प्रयुक्त होता है। होलोकॉस्ट रूपी दर्दनाक घटना के बाद यहूदी समुदाय ने अपनी पहचान एवं संस्कृति को जिंदा रखने की दिशा में काम किया। भयंकर उत्पीड़न के उस नाज़ी दंश को ज़ेहन में ताज़ा रखते

हुए, एक जुलता, आत्मविश्वास, जिजीविषा एवं पुनर्निर्माण के संकल्प को जिंदा रखा। होलोकॉस्ट की घटना यहूदियों के राष्ट्र प्रेम को और मजबूत करती है। 1948 में हुई आधुनिक इजरायल की स्थापना भी इसी का परिणाम है। 1959 में इजरायल की राष्ट्रीय विधायिका नेसेट ने प्रतिवर्ष 'होलोकॉस्ट स्मरण दिवस' मनाने की घोषणा की, ताकि नाज़ी अत्याचारों की यह दारुता उन्हें हमेशा याद रहे।

आज मध्य-पूर्व सुलग रहा है। इजरायल-ईरान में भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ है। चाहे तेल अवीव हो या तेहरान दोनों ओर के आम नागरिक मारे जा रहे हैं या विस्थापन को मजबूर हैं। इजरायल-ईरान जंग के बहाने अमरीका ईरान के परमाणु संवर्धन कार्यक्रमों पर रोक लगाना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस युद्ध के बखस हो सकता है, पदों के पीछे ईरान में तख्तापलट की पटकथा भी लिखी जा रही हो! बहरहाल, मनुष्यता दांव पर लगी है। संवाद कराने की बजाय, क्या मध्य-पूर्व के बहाने हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं? इन विकट हालातों के बीच कवि बिलाल पटान 'आरकोडिगाम' की एक कविता ज़ेहन में ध्वनित हो रही है- युद्धों के निर्णय हमेशा शून्य आते हैं; एक दिन आग से मुठभेड़ करते हुए, पानी मारा गया/ और एक दिन पानी से मुठभेड़ करते हुए, आग मारी गई।'

नजरिया

शिक्षा ने यह दिखाई, अब नेतृत्व की बारी

सोमन लववंशी
मोबाइल : 70008 54500

यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी रिपोर्ट 2024 जब यह कहती है कि लड़कियों की शैक्षणिक प्रगति वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय रही है, तो यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, एक उम्मीद का सिरा है। भारत में भी यह बदलाव साफ नजर आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक शिक्षा के निगमों से लेकर उच्च शिक्षा तक लड़कियों की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी अब 49 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है। यह एक ऐसा तथ्य है जो न केवल भारत के भविष्य की दिशा तय करता है, बल्कि सामाजिक संरचना में बदलाव के संकेत भी देता है, किंतु इस उजाले के साथ एक लंबी छाया खिंचती है। जब बात नेतृत्व की होती है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट की ऊँचाइयों या तकनीकी दुनिया के निगमों के मोर्चे, महिलाएं यहाँ बहुत पीछे खड़ी नजर आती हैं। केवल 7.2 प्रतिशत भारतीय कंपनियों में महिलाएं सीईओ पद पर हैं। संसद में उनकी भागीदारी 14 प्रतिशत से भी कम है। वैश्विक स्तर पर यह आंकड़ा थोड़ा ही बेहतर है। विश्व बैंक की साल 2024 की रिपोर्ट की माने तो, विश्वभर में शीर्ष नेतृत्वकारी पदों में केवल 10 प्रतिशत हिस्सेदारी महिलाओं की है। यह आंकड़े न सिर्फ स्थिति की गंभीरता बताता हैं, ये सवाल भी उठाता हैं कि आखिर क्यों शिक्षा में आगे निकल चुकी महिलाएं नेतृत्व के पायदान पर नहीं उठ पाई हैं? यह सवाल और भी गंभीर तब हो जाता है, जब

हम मातृसत्तात्मक समाज की बात करते हैं। मेघालय इतना ज्वलंत उदाहरण है। यहाँ खासी और जयंतिया जनजातियों में संपत्ति और वंशानुक्रम महिलाओं से जुड़ा है। इन सबके बावजूद इस राज्य की विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम या यूँ कहें नाममात्र ही है। ऐसे में यह विस्मयजनक है, या महिलाएं स्वयं नेतृत्व से दूर रहना चाहती हैं? शायद सत्य इन दोनों के बीच कहीं छिपा है, क्योंकि देश के बाकी हिस्सों की स्थिति भी काफी दयनीय है। पितृसत्तात्मक, सामाजिक अपेक्षाएं, और कार्यस्थलों पर मौजूद लैंगिक भेदभाव की संरचनाएं मिलकर एक ऐसा वातावरण निर्मित करती हैं, जहाँ महिलाएं नेतृत्व के अवसरों से वंचित रह जाती हैं। अवसर मिलने पर भी उन्हें दुर्लभा संघर्ष करना होता है। राजनीति जैसे क्षेत्र में तो यह और भी कठिन हो जाता है, जहाँ जोखिम, सार्वजनिक आलोचना, और कभी-कभी हिंसा तक का सामना करना पड़ता है। विश्व आर्थिक मंच की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि कार्यबल में वैश्विक रूप से महिलाओं की भागीदारी 42 प्रतिशत है, लेकिन विश्व नेतृत्व में यह संख्या घटकर केवल 31.7 प्रतिशत रह जाती है। इसी प्रकार, स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित) क्षेत्रों में महिलाओं की वैश्विक भागीदारी मात्र 28.2 प्रतिशत है। इसका अर्थ यह है कि महिलाएं केवल शिक्षा तक सीमित नहीं, ज्ञान के अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अनेकरी का शिकार हैं। वेतन असमानता भी एक बड़ी बाधा है। विश्व बैंक की वीमेन, बिजनेस एंड द लॉ-2024 की रिपोर्ट बताती है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की

तुलना में 2.4 घंटे अधिक अवैतनिक देखभाल कार्य करती हैं। इसके अतिरिक्त, 98 देशों में समान वेतन के कानून तो हैं, लेकिन केवल 35 देशों में ही ऐसे कानूनों के प्रवर्तन और पारदर्शिता के लिए मजबूत कानूनी ढांचा है। इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और नेतृत्वकारी भूमिका पर पड़ता है। इन सबके बावजूद, तस्वीर पूरी तरह धुंधली नहीं है। बदलाव की किरणें मौजूद हैं। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण दिए जाने के बाद से स्थानीय स्तर पर नेतृत्व में उनकी भागीदारी में सुधार देखा गया है। यह दिखाता है कि जब अवसर और संरचना दोनों सकारात्मक रूप में मिलते हैं, तो महिलाएं नेतृत्व में भी उत्कृष्टता दिखा सकती हैं। वैश्विक स्तर पर भी प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व बैंक की जेंडर स्ट्रेटेजी 2024-2030 का लक्ष्य है कि 2030 तक 300 मिलियन महिलाओं को डिजिटल कनेक्टिविटी, 250 मिलियन को सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क और 80 मिलियन महिला-नेतृत्व वाले व्यवसायों को वित्तीय समर्थन दिया जाए। ये योजनाएं महिलाओं को सशक्त करने के प्रयास नहीं, एक समावेशी भविष्य की नींव हैं। सवाल यह है कि इस नींव पर हम कैसे निर्माण करेंगे? सबसे पहले तो जरूरी है कि समाज में गहराई तक समाई लैंगिक रुढ़ियों को तोड़ा जाए। यह काम केवल पाठ्यक्रम बदलने या पोस्टर लगाने से नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि बचपन से ही लड़के और लड़कियों दोनों को समानता, नेतृत्व और सह-अस्तित्व के मूल्यों की शिक्षा दी जाए। कार्यस्थलों पर भी व्यापक बदलाव जरूरी है। मातृत्व अयकाश, लचीली कार्य व्यवस्था, यौन उत्पीड़न के मामलों में सख्त कार्यवाही, और

महिलाओं की पदोन्नति के लिए पाठ्यपुस्तकें और न्यायसंगत प्रणाली का निर्माण अनिवार्य है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए रिजर्व आरक्षण पर्याप्त नहीं होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण सांकेतिक न रहे, बल्कि उसके माध्यम से वास्तविक और प्रभावी नेतृत्व उभर कर सामने आए। इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण, संसाधन और एक सुरक्षित सार्वजनिक वातावरण प्रदान करना होगा। समाज को यह समझने की आवश्यकता है कि महिलाओं का नेतृत्व महिलाओं के लिए नहीं, पूरे समाज के विकास के लिए जरूरी है। जिन क्षेत्रों में महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, वहाँ निर्णय प्रक्रिया अधिक समावेशी, दीर्घकालिक और मानवीय दृष्टिकोण वाली रही है। महिलाओं की शिक्षा में हो रही प्रगति सराहनीय है, लेकिन यह तब तक अधूरी है जब तक नेतृत्व की ऊँचाइयों तक न पहुंचे। जब एक शिक्षित लड़की केवल एक नौकरी ही नहीं, बल्कि एक संस्था, एक आंदोलन, या एक नीति का नेतृत्व करती है, तभी हम कह सकते हैं कि शिक्षा ने अपना उद्देश्य पूरा किया है। समाज को यह स्वीकारना होगा कि नेतृत्व कोई जन्मगत विशेषाधिकार नहीं, अर्जित किया गया दायित्व है और जब तक महिलाओं को इस दायित्व को निभाने का पूरा अवसर नहीं मिलेगा, तब तक हम एक सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील राष्ट्र नहीं बन सकते। अतः यह समय केवल आंकड़ों की तालिका सजाने का नहीं, उन आंकड़ों को जीने और बदलने का है। यह समय है कि हम लड़कियों की शिक्षा से आगे बढ़कर उन्हें नेतृत्व के मंच तक पहुंचाएं, क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तो समाज भी आगे बढ़ता है।

दक्षिण भारत राष्ट्रमत

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष बढ़ने के संकेतों के बीच ट्रंप जी-7 छोड़ अमेरिका के लिए रवाना

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

वाशिंगटन/एपी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी-7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के साथ तत्काल वार्ता के लिए सोमवार को स्वदेश रवाना हो गए।

ट्रंप ने तेहरान के 95 लाख निवासियों से अपनी जान बचाने के लिए वहां से चले जाने का आग्रह किया है। इसके साथ ही उन्होंने ईरान के साथ परमाणु समझौता संभव होने की बात भी कही है।

संभावना है कि वह मंगलवार को व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। पांच दिनों से जारी मिसाइल हमलों से इजराइल ने ईरान को काफी नुकसान पहुंचाया है और उसे लगता है कि अब वह तेहरान के परमाणु कार्यक्रम को रथायी झटका दे सकता है- खासकर अगर उसे ट्रंप से थोड़ी और मदद मिले।

ट्रंप ने वाशिंगटन लौटने के दौरान 'एयर फोर्स वन' में संवाददाताओं से कहा, "ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता।" उन्होंने ईरानी नेताओं पर अपने परमाणु कार्यक्रम पर किसी समझौते पर पहुंचने के लिए अनिच्छुक होने का आरोप लगाया और सुझाव दिया कि अब उनकी उनसे बातचीत करने में दिलचस्पी घट गई है। ट्रंप ने कहा, "हम युद्धविराम

समझौता कर लेना चाहिए था। मैंने उनसे कहा, समझौता कर लो। इसलिए मुझे नहीं पता।" बातचीत करने के मूक नहीं हूँ।"

राष्ट्रपति ट्रंप अपने सलाहकारों से मिलने वाले हैं, जिससे संकेत मिलता है कि संघर्ष में अमेरिका की प्रत्यक्ष भूमिका बढ़ने वाली है। उनके रुब में बदलाव ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने क्षेत्र में युद्धपोतों और सैन्य विमानों को फिर से तैनात किया है ताकि अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ता है तो वे उसका जवाब दे सकें।

इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष तेज होने के मद्देनजर ट्रंप कनाडा के कर्नेलिकस में आयोजित जी-7 शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका के लिए रवाना हो गए।

ट्रंप ने दिन में कई बार यह बात दोहराई कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में फिर से इस बात पर जोर दिया, जिसमें उन्होंने लिखा, "ईरान परमाणु हथियार नहीं बना सकता।"

निकासी के बारे में पूछे जाने पर ट्रंप ने 'एयर फोर्स वन' में संवाददाताओं से कहा कि "मैं बस यही चाहता हूँ कि लोग सुरक्षित रहें।" उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों का यह कहना गलत है कि अमेरिका युद्ध विराम पर काम कर रहा है। ट्रंप ने कहा, "हम युद्धविराम

से बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं। हम युद्ध विराम की उम्मीद नहीं कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि मैक्रों एक "अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन वे अक्सर सही निर्णय नहीं ले पाते।"

ट्रंप ने कहा कि वह कूटनीतिक विकल्प से इनकार नहीं कर रहे हैं, और वह उपराष्ट्रपति जे डी वेंस और विशेष दूत स्टीव वित्कोफ को ईरानियों से मिलने के लिए भेज सकते हैं।

उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे लौटने पर क्या होता है।" उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबाई की कांग्रेस के समक्ष गवाही को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने मार्च में सांसदों से कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को विश्वास नहीं था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ट्रंप ने कहा, "मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने (तुलसी) क्या कहा। मुझे लगता है कि वे (ईरान) इसे हासिल करने के बहुत करीब थे।"

इजराइल का कहना है कि उसके हमले ने ईरान की हवाई सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया है और अब वे देश भर में कहीं भी हमला कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल की बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट नहीं हो जातीं।

ईरान में कुछ भारतीय विद्यार्थी स्वदेश वापसी के इंतजार में, अन्य को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया

नई दिल्ली/भाषा

ईरान के 'तेहरान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय' में भारतीय छात्र मेहरीन जफर हवाई हमले के सायरन की आवाजों और बिजली गुल हो जाने के बीच डर के साये में जी रही है। वह उन 70 से अधिक भारतीय विद्यार्थियों में एक है जो ईरान से निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल ईरान और इजराइल के साथ भीषण सैन्य संघर्ष चल रहा है।

मेहरीन ने कहा, "हम मदद के लिए पुकार रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। हमें कुछ भी पता नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें यहां से निकाला जाए।" उसने कहा, "हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से पूरी उम्मीद है और हमें मदद की जरूरत है। हम

ऐसे नहीं रह सकते।" केरमान चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के 21 वर्षीय छात्र फैजान नबी ने कहा कि उसने अपना सामान पैक करना शुरू कर दिया है।

उसने कहा, "यहां (केरमान) स्थिति तेहरान जितनी खराब नहीं है। लेकिन अब भी डर बना हुआ है। हमें उम्मीद है कि हमें जल्द ही किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाएगा।"

हालांकि 'उर्मिया चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय' के छात्र हुजेफ मलिक उन विद्यार्थियों में से एक थे जिन्हें भारतीय अधिकारियों ने आर्मेनिया पहुंचाया है। उसने कहा, "हम उर्मिया में थे जो

अपेक्षाकृत सुरक्षित था। हम आर्मेनिया पहुंच गए हैं।"

इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच, तेहरान से भारतीय विद्यार्थियों को निकाल लिया गया है। उनमें से 110 द्वावासा द्वारा की गई व्यवस्था के माध्यम से सीमा पार करके आर्मेनिया पहुंच गए हैं।

जम्मू-कश्मीर छात्र संघ के अनुसार, ईरान-आर्मेनिया सीमा पार करने वाले सभी भारतीय विद्यार्थी अब सुरक्षित रूप से राजधानी गेरेवन पहुंच गए हैं। उन्हें उनके निधार्ित स्थान पर हटवाया गया है।

उन्होंने कहा, "यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे लौटने पर क्या होता है।" उन्होंने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबाई की कांग्रेस के समक्ष गवाही को भी खारिज कर दिया, जिन्होंने मार्च में सांसदों से कहा था कि अमेरिकी जासूसी एजेंसियों को विश्वास नहीं था कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है। ट्रंप ने कहा, "मुझे परवाह नहीं कि उन्होंने (तुलसी) क्या कहा। मुझे लगता है कि वे (ईरान) इसे हासिल करने के बहुत करीब थे।"

इजराइल का कहना है कि उसके हमले ने ईरान की हवाई सुरक्षा को तहस-नहस कर दिया है और अब वे देश भर में कहीं भी हमला कर सकते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि इजराइल की बमबारी तब तक जारी रहेगी जब तक ईरान का परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलें नष्ट नहीं हो जातीं।



कमल हासन से सराहना पाकर अभिषेक बनर्जी हुए भावुक

मुंबई/एजेन्सी

बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बनर्जी, कमल हासन से सराहना पाकर भावुक हो गए। अभिनेता अभिषेक बनर्जी इन दिनों अपनी फिल्म स्टोलन में शानदार अभिनय के लिए खूब सराहे जा रहे हैं। हाल ही में उन्हें एक ऐसा पल मिला जो उनके करियर के सबसे खास और यादगार पलों में से एक बन गया। चैन्नई में एक खास प्राइवेट स्क्रीनिंग के दौरान कमल हासन ने देखा और पूरी टीम को इतनी बेहतरीन फिल्म बनाने के लिए बधाई दी। अपने बेहतरीन सिनेमा और शानदार नजरिए के लिए पहचाने जाने वाले कमल हासन ने न सिर्फ फिल्म की कहानी को सराहा बल्कि अभिषेक बनर्जी के प्रदर्शन की भी

दिल खोलकर तारीफ की। स्टोलन की टीम, जिसमें अभिषेक भी शामिल थे, ने खुद चैन्नई जाकर यह फिल्म कमल हासन को दिखाई।

इस खास पल को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा, "मैंने कमल हासन सर की फिल्म में देखकर ही अभिनय करना सीखा है। वो एक जीते-जागते महान कलाकार हैं और हम जैसे कलाकारों के लिए हमेशा प्रेरणा रहे हैं। स्टोलन के लिए उनसे तारीफ मिलना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। यह पल मेरे दिल में हमेशा के लिए बसा रहेगा। स्टोलन को दर्शकों और समीक्षकों से लगातार शानदार प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं और अब कमल हासन की इस मान्यता से फिल्म की सफलता को और मजबूती मिली है।"

मेहुल चोक्सी ने ब्रिटेन की अदालत में भारत के खिलाफ 'अपहरण' का आरोप लगाया

लंदन/भाषा

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांचित व्यवसायी मेहुल चोक्सी ने लंदन के उच्च न्यायालय में भारत सरकार और पांच व्यक्तियों पर अपने कथित 'अपहरण, यातना और प्रत्यर्पण के प्रयास' के लिए ध्वजकारि के रूप में मुकदमा दायर किया है।

भारतीय प्राधिकारियों ने आरोपों से इनकार किया है और 'राज्य प्रतिरक्षा' (स्टेट इन्फ्यूनिटी) के आधार पर ब्रिटेन के क्षेत्राधिकार पर आपत्ति जताई है। साथ ही उन्होंने भारतीय कानून और भारतीय संविधान से संबंधित विशेषज्ञ साक्ष्यों को ध्यान में रखने की अनुमति भी मांगी है।

राज्य प्रतिरक्षा अंतरराष्ट्रीय कानून का सिद्धांत है, जिसके अनुसार एक स्वतंत्र राष्ट्र को दूसरे देश की अदालत में न्यायिक कार्यवाही से छूट प्राप्त होती है। सोमवार को न्यायमूर्ति फ्रीडमैन के समक्ष मामले की प्रारंभिक सुनवाई के दौरान, अदालत को बताया गया कि चोक्सी का दावा है कि ई 2021 में "भारत सरकार के निर्देश पर" अपहरण की कोशिश

के तहत उसे प्रताड़ित किया गया था। भारतीय पक्ष ने इस सप्ताह अदालत को बताया कि चोक्सी ने "भारत के खिलाफ बेदर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें कहा गया है कि भारत ने उसका अपहरण करने और नुकसान पहुंचाने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश रची थी।"

वकील हरीश साल्वे ने भारतीय अधिकारियों की ओर से दलील दी, "भारत का पक्ष यह है कि वर्तमान दावा मुख्य रूप से इस संज्ञा से आगे बढ़ाया जा रहा है कि भारत को शर्मिंदा किया जाए और प्रतिवादी द्वारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रत्यर्पण से बचने के प्रयासों के तहत दबाव बढ़ाया जा सके।" वकील एडवर्ड फिट्जजेराल्ड के नेतृत्व में चोक्सी के वकीलों ने आरोप लगाया कि एंटीगुआ में उस पर हमला करने में पांच व्यक्तियों के बीच मिलीभगत थी, ताकि उसे जब्त कर भारत को सौंपने के उद्देश्य से कैरेबियाई देश जामिनिका ले जाया जा सके। चोक्सी की दलील में कहा गया, "प्रतिवादिनों ने एक गैरकानूनी ध्वजत्र रचा, जिसके तहत प्रतिवादिनों ने याचिकाकर्ता पर हमला, मारपीट, गलत कारावास, गैरकानूनी हिरासत

और आयाजाही पर गैरकानूनी प्रतिबंध के माध्यम से हानिकारक कार्य करने पर सहमति व्यक्त की और फिर ऐसा किया।" चोक्सी बेलजियम में हिरासत में हैं, और भारत में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। चोक्सी का भांजा नीरव मोदी भी भारत में वांचित है। वह लंदन में सलाखों के पीछे है। नीरव मोदी भी ब्रिटेन की अदालतों से कई बार जमानत की गुहार लगा चुका है, लेकिन उसे राहत नहीं मिली है। भारत में नीरव मोदी के खिलाफ तीन तरह की आपराधिक कार्यवाही चल रही है। पीएनबी के साथ धोखाधड़ी का केंद्रीय अन्वेषक ब्यूरो (सीबीआई) का मामला, उस धोखाधड़ी की आय के कथित शोषण से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का मामला और सीबीआई की कार्यवाही में साक्ष्य और गवाहों को प्रभावित करने से संबंधित आपराधिक कार्यवाही का तीसरा मामला है। अप्रैल 2021 में, ब्रिटेन की अदालतों में इन आरोपों का सामना करने के लिए उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया था।



फिल्म 'कुबेरा' का ट्रेलर रिलीज

मुंबई/एजेन्सी

दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार धनुष की आने वाली फिल्म कुबेरा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। उराष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक शेखर कम्मला की फिल्म कुबेरा में धनुष, नागार्जुन अकिनेनी, रंशिका मंदाना और जिम सर्भकी अहम भूमिका हैं। धनुष का किरदार पावर और पैसे की अंधी दौड़ में है, जहां रुकना मना है, और नैतिकता तो दूर-दूर तक नहीं दिखती। वहीं दूसरी तरफ नागार्जुन

का 'देवा' है जो अपनी मंजिल बिना हिंसा के पाना चाहता है। यानी लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं, अंदरूनी भी है। रंशिका मंदाना का रोल इस इंटेंस कहानी में एक प्यारी सी सांस की तरह है जो इमोशन का तड़का लगाती है। और फिर आते हैं जिम सर्भ, जो हर फ्रेम में सरप्राइज एलिमेंट की तरह लगते हैं। ट्रेलर में मिलती हैं घमाकंदार एक्शन सीन्स, चुभते हुए धोखे और करारा इमोशनल पंच और इसमें जान डालते हैं निकेत बोम्मिरेड्डी की शानदार सिनेमैटोग्राफी और

डीएसपी यानी देवी श्री प्रसाद का धड़कता हुआ म्यूजिक। शेखर कम्मला ने इस फिल्म के जरिए पावर, लालच और नैतिकता के सवाल को जिस अंदाज में पेश किया है, वो काबिल-ए-तारीफ है। खासकर नागार्जुन और धनुष के बीच की केमिस्ट्री जबरदस्त है। श्री वेंकटेश सिनेमा एलएपी और एमिगोस क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत इस फिल्म का निर्माण सुनील नाराय और पुष्कर राम मोहन राव ने किया है। विपुल अग्रवाल और मनीष वरिह सह निर्माता हैं।

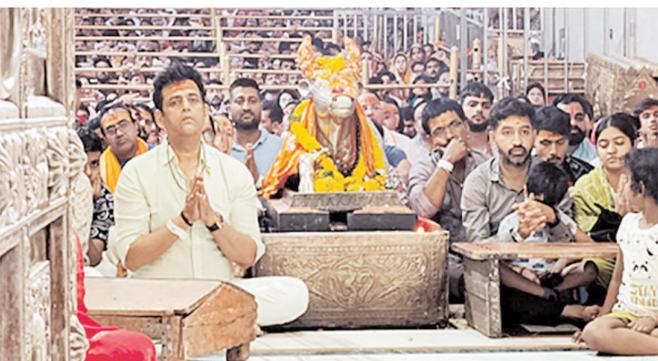


म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट में हुई 'महावतार नरसिंह' की स्क्रीनिंग

बेल्जियम/एजेन्सी

बेल्जियम के डब्ल्यू शहर में बने म्यूजियम ऑफ सेक्रेड आर्ट (मोसा) में एक खास आयोजन हुआ, जहां 'महावतार नरसिंह' की स्क्रीनिंग रखी गई। इस मौके पर आध्यात्मिकता और सिनेमा का शानदार संगम देखने को मिला, जिसे दुनियाभर से आए लोगों ने देखा और सराहा। भावान विष्णु के नरसिंह अवतार पर बनी इस एनिमेटेड कहानी ने लोगों का दिल छू लिया। आधा आदमी, आधा शेर वाले इस रूप की कथा को जिस तरह दिखाया गया, उसकी भावनाएं, कला और कहानी सब कुछ इतना जबरदस्त था कि देखने वाले भावुक होने के साथ दंग रह गए। महावतार नरसिंह के ऑफिशियल हैंडल पर लिखा गया मोसा, बेल्जियम में गूंजा

अंतरराष्ट्रीय तालियों का शोर! महावतार नरसिंह की गर्जना सरदरों से पाए गूंज उठी। महावतार नरसिंह को होम्बले फिल्मस ने बनाया है, जो अब तक कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों के चुका है। महावतार नरसिंह का निर्देशन अश्विन कुमार ने किया है और इसे शिल्पा धवन, कुशल देसाई और चैतन्य देसाई ने क्लीम प्रोडक्शंस के बैनर तले बनाया है। इसमें होम्बले फिल्मस का भी साथ है, जो अब तक के कई बड़े हिट फिल्मों के लिए जानी जाती है। इस दमदार जोड़ी का मकसद है दर्शकों के सामने एक ऐसी फिल्म पेश करना जो हर मायने में शानदार हो। जबरदस्त विजुअल्स, भारतीय संस्कृति की झलक, जोरदार कहानी और बढ़िया सिनेमाई अंदाज के साथ ये फिल्म उऊमें और पांच भारतीय भाषाओं में रिलीज की जाएगी।



महाकालेश्वर के दर्शन को उज्जैन पहुंचे रवि किशन, भस्म आरती में हुए शामिल

उज्जैन/एजेन्सी

अभिनेता, भाजपा सांसद रवि किशन सोमवार को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा का दर्शन-पूजन किया। रवि किशन भस्म आरती में भी शामिल हुए। उन्होंने भावान महाकाल के दर्शन-पूजन किए और मंदिर परिसर में विकसित महाकाल कॉरिडोर की जमकर तारीफ की। रवि किशन ने कहा, इतना भव्य महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए मैं प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, पीएम मोदी और उबल इंजन सरकार का आभारी हूँ। श्रद्धालुओं के लिए अब अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अहमदाबाद विमान हवाई को लेकर उन्होंने कहा, भावान महाकाल इस दुख को हरे और हावसे में मृत लोगों की आत्मा को शांति मिले। यही

अर्जी लगाने आया हूँ। पूजन, अर्पित पुजारी ने सम्पन्न करवाया। वहीं, श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने रविकिशन का स्वागत व सम्मान किया। रवि किशन ने नंदी हॉल से शिव साधना की चांदी से माथा टेक आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचे रवि किशन पीले रंग का 'महाकाल' के नाम का दुपट्टा ओढ़े और माथे पर रोली का तिलक लगाए नजर आए।

रवि किशन ने दर्शन के बाद कहा, महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन कर मन को अपार शांति मिली। इतना भव्य और सुंदर महाकाल कॉरिडोर बनाने के लिए मैं स्थानीय प्रशासन, मध्य प्रदेश सरकार, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और उबल इंजन सरकार का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। अब श्रद्धालुओं के लिए यहां विश्वस्तरीय सुविधाएं

उपलब्ध हैं, जिससे दर्शन और अधिक सुगम और सुखद हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा, महाकाल कॉरिडोर परियोजना न केवल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान कर रही है। यह कॉरिडोर उज्जैन की शान बढ़ाने के साथ-साथ लाखों भक्तों के लिए आस्था का नया केंद्र बन गया है। मैं महाकालेश्वर समिति का भी आभार जताता हूँ। महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साल 2022 में किया था। इससे मंदिर परिसर को भव्य और आधुनिक स्वरूप प्रदान किया गया है। परियोजना के तहत मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र को विकसित किया गया है, जिसमें भक्तों के लिए बेहतर दर्शन व्यवस्था, विश्राम स्थल, स्वच्छता और अन्य सुविधाएं भी शामिल हैं।

सायरा की 'अम्मी' नसीम बानो, जिनकी फिल्म देखने लोग जूते उतार कर जाते थे

मुंबई/एजेन्सी

भारतीय सिनेमा की 'पहली सुपरस्टार', 'पहली रानी' और 'परी-चेहरा' नाम से जानी जाती हैं नसीम बानो। 18 जून को हिंदी सिने जगत की मशहूर हस्ती की पुण्यतिथि है। 4 जुलाई 1916 को पुरानी दिल्ली में जन्मी नसीम बानो ने 1930 और 1940 के दशक में अपनी खूबसूरती और अभिनय की ताकत से सिनेमा जगत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। जब हिन्दी सिनेमा में स्वर्णलता, मुमताज शांति और नूरजहां सरिखी अभिनेत्रियों का बोलबाला था, तब भी नसीम की चमक फीकी नहीं पड़ी। गजब की खूबसूरत थीं, इस बात का जिक्र साहित्यकार,

उपन्यासकार सआदत हसन मंटो ने अपनी एक रचना में भी किया था। उन्होंने नसीम की तारीफ में लिखा, उन दिनों अभिनेत्रियों में से एक थीं नसीम बानो, जो खारा मशहूर थीं। खूबसूरती की बहुत चर्चा थी। इतिहास में 'परी चेहरा नसीम' कहा जाता था। मैंने अपने ही अखबार में उसके कई फोटो देखे थे। खुश शकल थीं, जवान थीं। खासतौर पर आंखें बड़ी पुर-कशिश थीं और जब आंखें पुर-कशिश हों तो सारा चेहरा पुर-कशिश बन जाता है।

संगीतकार नीशाद ने उन्हें 'परी-चेहरा' उपनाम दिया, जो उनकी खूबसूरती और आभा का प्रतीक बना। दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गजों ने



अभिनेत्री की है, बल्कि एक ऐसी महिला की है, जिसने अपने समय की रुढ़ियों को तोड़ा और भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ी।

नसीम बानो का जन्म रोशन आरा बेगम के रूप में एक ऐसे परिवार में हुआ, जहां कला और संगीत की गहरी जड़ें थीं। उनकी मां चमियान बाई, जिन्हें शमशाद बेगम के नाम से भी जाना जाता था, उस दौर की मशहूर गायिका और तवायफ थीं। नसीम की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने क्रीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां चाहती थीं कि वह डॉक्टर बनें, लेकिन नसीम का दिल तो सिनेमा में बसता था, और उनकी धड़कन उसी के लिए धड़कती थी। अभिनेत्री सुनोचना

की प्रशंसक नसीम का सपना था कि वह भी बड़े पद पर चमके। इस सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत तब हुई, जब बाँम्बे की एक यात्रा के दौरान सोहराब मोदी ने उन्हें अपनी फिल्म 'खून का खून' में अभिनय के लिए बुलाया। हालांकि, नसीम की मां नहीं चाहती थीं कि उनकी लाडली बेगम के नाम से भी जाना जाता था, उस दौर की मशहूर गायिका और तवायफ थीं। नसीम की परवरिश दिल्ली में हुई, जहां उन्होंने क्रीन मैरी हाई स्कूल में पढ़ाई की। उनकी मां चाहती थीं कि वह डॉक्टर बनें, लेकिन नसीम का दिल तो सिनेमा में बसता था, और उनकी धड़कन उसी के लिए धड़कती थी। अभिनेत्री सुनोचना

